घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 166- शनिवार 18 - अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

उन्नाव,चित्रकूट और प्रयागराज में तीन घरों में लगी भीषण आग

3 बच्चियों की मौत

कानपुर,17 अप्रैल 2026। उन्नाव व चित्रकूट में घरों में लगी आग की चपेट में आकर दो बच्चियों की जलकर मौत हो गई। चित्रकूट में शिवकुमार के घर शार्ट-सर्किट से आग लग गई। जिसमें मासूम की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। उन्नाव में संदीप कुमार की पत्नी लक्ष्मी अपनी तीन साल की बेटी लाडो को घर में सुलाकर मोहल्ले में ही छठी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी,तभी मोमबत्ती लुढ़ककर गिरने से आग लगी। ग्रामीणों ने आग बुझाई व गंभीर रूप से झुलसी बच्ची को सीएचसी नवाबगंज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उधर प्रयागराज के एयरपोर्ट क्षेत्र के इंगुआ उर्फ काठगांव निवासी राम सिंह रैदास ने गांव की आबादी से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में घास फूस और प्लास्टिक की पन्नी का छप्परनुमा घर बनवा रखा था

अब विदेशों से भी चंदा ले सकेगी धीरेंद्र शास्त्री की संस्था

गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्ली,17 अप्रैल 2026। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रजिस्ट्रेशन दे दिया है। इसके बाद अब यह संस्था विदेशों से मिलने वाले चंदे को कानूनी रूप से स्वीकार कर सकेगी। यह संस्था पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में काम करती है, जो देशभर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। अब तक इस संस्था को विदेशी फंड लेने की अनुमति नहीं थी लेकिन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद इसके लिए रास्ता खुल गया है। दरअसल, भारत में कोई भी एनजीओ या धार्मिक-सामाजिक संस्था अगर विदेश से पैसा लेना चाहती है, तो उसे पहले सरकार से एफसीआरए की अनुमति लेनी होती है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से हो और उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। अनुमति मिलने के बाद ही कोई संस्था सामाजिक,धार्मिक,शैक्षिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए विदेशी दान ले सकती है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को अब कई कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन मिला है, जिसमें धार्मिक (हिंदू),सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अब संस्था इन सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए विदेशों से फंड प्राप्त कर सकती है।

भोंदू बाबा अशोक खरात मामले के अहम गवाह की सड़क हादसे में मौत...

नई दिल्ली,17 अप्रैल 2026। भोंदू अशोक खरात मामले के अहम गवाह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। समृद्धि महामार्ग पर हुए भीषण हादसे में इस मामले के महत्वपूर्ण गवाह डॉ. जितेंद्र शेलके की जान चली गई। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी अनुराधा शेलके की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार, डॉ. शेलके शनिवार दोपहर अपने परिवार के साथ छत्रपति संभाजीनगर से शिर्डी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान धोत्रे गांव के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सीधे कंटेनर के नीचे घुस गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद काफी समय तक कार कंटेनर के नीचे फंसी रही। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया,लेकिन तब तक डॉ. शेलके और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। वहीं, उनके बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया,जहां उसका इलाज जारी है।

मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम, 528 सांसदों ने वोट डाला

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा...पक्ष में 298,विपक्ष में 230 वोट पड़े

नई दिल्ली,17 अप्रैल 2026। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया। 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने एक घंटा स्पीच दी थी। कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखें, इनमें 56 महिला सांसद थीं।

शाह बोले...विपक्ष बिना सोचे-समझे बस विरोध कर रहे हैं...

शाह ने कहा...विपक्ष ने अच्छा बुरा सोचे बिना मोदी जी जो करे रहे हैं,उसका विरोध करने का ठान लिया है। देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है तो लग रहा था विरोध नहीं होगा। लेकिन हो रहा है। मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ लेकिन आज कांग्रेस पीछे हट रही है। इसके दो ही कारण हैं-क्योंकि बिल मोदी जी ला रहे हैं और क्रेडिट उन्हें मिलेगा। मोदी जी ने उन्हें एड देकर क्रेडिट देने का कह दिया फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि अंतरआत्मा की आवाज से वोट करिए। अंतरआत्मा की आवाज का नारा इंदिरा जी का है। यहां आत्मा ही नदारद है। चुनाव में जहां जहां जाओगे,महिलाओं का आक्रोश फेस करना पड़ेगा। शाह ने कहा...हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए,उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी सामना करना पड़े।

यह सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के गिरने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा 'आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना,उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।' उन्होंने लिखा 'अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार-बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को 'महिलाओं का आक्रोश' न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में,बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।'

राहुल बोले...हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा,हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया है। हमने साफ तौर पर कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है,बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है।

रवि किशन बोले...संघर्ष में पत्नी ने दिया साथ,इसलिए करता हूं सम्मान

भाजपा सांसद रवि किशन ने अपनी पत्नी को लेकर कहा कि उनके राजनीतिक प्रचार से लेकर जमीनी समर्थन तक में उनकी पत्नी की अहम भूमिका रहती है। रवि किशन ने कहा कि 'मेरा प्रचार भी मेरी पत्नी करती हैं। मेरा एक डेढ़ लाख वोट पत्नी लाती हैं। मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं। क्यों न छुएं उसने मेरी गरीबी और स्ट्रगल में साथ दिया। हालांकि वो छूने नहीं देती मैं उनके सोते हुए पैर छू लेता हूं।' उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा 'यहां लोग अपने गार्डन की कहानी सुनाकर चले गए। पीएम का अपमान कर गए।

संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों का प्रदर्शन

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पारित नहीं हो पाने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। महिला आरक्षण से जुड़े इस विधेयक के असफल रहने पर सांसदों ने नाराजगी जताई और इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।

महिलाएं कांग्रेस को माफी नहीं करेंगी : रवि शंकर प्रसाद

बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी हर चीज का विरोध करते हैं। आज जब मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। तब वे (विपक्ष) इसका विरोध कर रहे हैं। यह साफ है कि वे 'नारी वंदन' और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। देश की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगी।

दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा...ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे सीबीआई

लखनऊ,17 अप्रैल 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। इस पर जज ने मंजूरी देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी।

याचिकाकर्ता का दावा हलफनामा महत्वपूर्ण

यह मामला पहली बार इस स्तर पर लखनऊ बेंच में विस्तार से सुना जा रहा है,जिसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखा है। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि दाखिल हलफनामा उनके आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

कोर्ट ने मंत्रालय से 'टॉप सीक्रेट' फाइलें ली

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाईकोर्ट में पेश कीं। मामले में याचिका दायर करने वाले विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए हैं,जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।

निचली अदालत के आदेश को चुनौती

यह याचिका आपराधिक प्रार्थना पत्र (क्रिमिनल एप्लिकेशन) के रूप में दाखिल की गई है, जिसमें 28 जनवरी 2026 को स्पेशल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने कोतवाली थाना, रायबरेली को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था, जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

गौतम अदाणी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली,17 अप्रैल 2026। देश के जाने-माने अरबपति उद्योगपति और अदाणी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदाणी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। गौतम अदाणी की कुल संपत्ति बढ़कर 92.6 अरब डॉलर हो गई है,जिससे वह वैश्विक स्तर पर 19 वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 90.8 अरब डॉलर रह गई है और वह 20वें स्थान पर खिसक गए हैं। शीर्ष स्तर पर हुए इस फेरबदल से भू-राजनीतिक तनाव और बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच 2026 में वैश्विक अमीरों की रैंकिंग में जारी अस्थिरता उजागर होती है। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार के सत्र में अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई,जिसने बेंचमार्क इंडेक्स को भी पीछे छोड़ दिया। इसी के चलते एक ही दिन में गौतम अदाणी की संपत्ति में करीब 3.56 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

कर्नाटक में सड़क हादसा...कार सवार परिवार के 6 छह सदस्यों की मौत

कर्नाटक,17 अप्रैल 2026। कर्नाटक के यादगिरि जिले के सुरपुर तालुक के देवापुर के पास कार और निजी बस के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार यादगिरि से रायचूर और कार और बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही थी। टक्कर के बाद कार और बस दोनों में आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन दल की टीम ने आग पर काबू पाया। मृतकों की पहचान रायचूर जिले के सिरवार कस्बे के निवासी काउंसलर कृष्णा नायक (50),उनकी पत्नी अनंत कला (45), शरणप्पा (36),उनकी पत्नी निसर्गा (30),पुत्र सिद्धार्थ (3) और शशिकला (30) के रूप में हुई है। यह सभी कार सवार हैं। बताया जा रहा है कि अमावस्या के अवसर पर वेणुगोपाल मंदिर के दर्शन कर लौटते समय यह हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार अश्विक (5) और एक वर्षीय श्रीनिधि चमत्कारिक रूप से बच गए। दोनों की हालत गंभीर है। उन्हें यादगिरि के यिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यादगिरि के पुलिस अधीक्षक पृथ्विक शंकर ने बताया कि कार में एक ही परिवार के आठ लोग सवार थे, जिनमें से छह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे घायल हो गए। कार के ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद बस कार को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस संबंध में सुरपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

झारखंड के हजारीबाग जिले में मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी शहदेव महतो सहित चार नक्सली ढेर

हजारीबाग,17 अप्रैल 2026। झारखंड के हजारीबाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में चार कुख्यात नक्सली मारे गए। इनमें 15 लाख रुपये का इनामी सहदेव महतो उर्फ अनुज (आरसीएम),महिला नक्सली नताशा (एस जेडसीएम),एरिया कमांडर बुधन करमाली (एसी) और रंजीत गंझू(एसी) शामिल है। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंडू खपियां गांव में हुए इस संयुक्त ऑपरेशन में कोबरा बटालियन और हजारीबाग पुलिस शामिल थी। सुरक्षाबलों ने मौके से 4 हथियार बरामद किए हैं। इनमें 2 एके 47 राइफल, एक इंसास राइफल शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। इस दौरान नक्सलियों ने खुद को घिरता देख सुरक्षाबलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस पर सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से घंटों चली मुठभेड़ में चार नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए।

हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने

पहली बार मनोनीत सदस्य को पद मिला,पीएम बोले...सदन को उन पर गहरा भरोसा है...

नई दिल्ली,17 अप्रैल 2026। हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। उन्हें शुक्रवार को निर्विरोध चुना गया हैं। विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं आया था। पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। हरिवंश के समर्थन में राज्यसभा सचिवालय को पांच प्रस्ताव मिले। सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहला प्रस्ताव रखा, जबकि दूसरा प्रस्ताव नितिन नवीन ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि सदन को आप पर गहरा भरोसा है। बीते समय में आपके अनुभव का सदन को लाभ मिला है। आपने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हुआ था। उनकी पार्टी जेडीयू ने इस बार नाम नहीं दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन किया। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद सीट खाली हुई थी। इसे भरने के लिए JDU के हरिवंश को चुना गया। वे 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे। दरअसल, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति तय करते हैं। इन्हें कला, साहित्य,विज्ञान और समाज सेवा में विशेष योगदान के आधार पर चुना जाता है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान राज्यसभा में रिटायर हो रहे सांसदों का विदाई समारोह 18 मार्च को हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने हरिवंश के लिए कहा था...'हमारे उपसभापति हरिवंश विदा ले रहे हैं। हरिवंश को इस सदन में लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर मिला।'पीएम मोदी ने हिंट दी थी कि हरिवंश की राजनैतिक पारी अभी खत्म नहीं हुई है, वे आगे भी जनहित में काम करते रहेंगे। इसके आधार पर ही यह माना जा रहा है हरिवंश नारायण को मनोनीत सांसद बनाकर दोबारा लाया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना केंद्र घटाकर 87 किए गए

कोलकाता,17 अप्रैल 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना केंद्रों की संख्या घटाकर 87 कर दी है। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में मतगणना केंद्रों की संख्या 90 थी,जिसे वर्ष 2021 में बढ़ाकर 108 किया गया था। इस बार आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इनकी संख्या घटाकर 87 कर दी गई है। इन 87 मतगणना केंद्रों में सबसे अधिक 12 केंद्र दक्षिण 24 परगना में बनाए गए हैं। इसके बाद उत्तर 24 परगना में आठ और हुगली में छह केंद्र होंगे। सबसे कम एक-एक केंद्र कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम में बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान 23 और 29 अप्रैल को होगा। मतगणना चार मई को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी बीच आयोग ने शुक्रवार को बताया कि मंगलवार रात नौ बजे तक कुल 18,38,572 संपत्ति विरूपण के मामलों को हटाया जा चुका है।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला,कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे

ट्रम्प बोले...शुक्रिया,भारत ने ईरान से 2,358 लोगों को निकाला

वॉशिंगटन डीसी,17 अप्रैल 2026। ईरान ने सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीजफायर के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है,ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अराघची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी,ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल गया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने अब तक ईरान से 2,358 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इन लोगों को ईरान से निकालकर आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचाया, जहां से उनकी भारत वापसी कराई जा रही है। ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड (संवर्धित) यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है।

तमिलनाडु चुनाव 2026 के बीच जब्ती 800 करोड़ के पार,2021 के मुकाबले लगभग दोगुनी

चेन्नई,17 अप्रैल 2026। तमिलनाडु में चल रहे चुनावी माहौल के अब तक करीब 800 करोड़ रुपए की नकदी, कीमती सामान और अवैध वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं। यह आंकड़ा 2021 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले लगभग दोगुना है। चुनाव विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 2021 के चुनाव में 446.28 करोड़ रुपए के उपहार और कीमती धातुएं बिना वैध दस्तावेज के जब्त की गई थीं। इसके अलावा 236.70 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी पकड़ी गई थी। खास बात यह रही कि जब्त किए गए सामान में से 50 प्रतिशत से ज्यादा बाद में सही दस्तावेज दिखाने पर लोगों को वापस लौटा दिए गए थे। उस समय कुल जब्ती में केवल सोने की हिस्सेदारी ही 173.19 करोड़ रुपए की थी। वहीं,इस बार स्थिति और ज्यादा सख्त नजर आ रही है। बुधवार तक करीब 800 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है, जिसमें नकदी,आभूषण, नशीले पदार्थ और शराब शामिल हैं।

संपादकीय

बिहार की राजनीति में भाजपा का प्रयोग

सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बहुस्तरीय घटना है...यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं,बल्कि एक संकेत है...भाजपा की बदलती रणनीति का,बिहार की राजनीति के नए चरण का और उस निरंतर संघर्ष का,जिसमें जाति, विकास,नेतृत्व और विचारधारा सब एक साथ उलझे रहते हैं...

बिहार की राजनीति सीधी रेखा में चलने वाली नहीं है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना केवल एक व्यक्ति का सत्ता में आना नहीं, बल्कि कई स्तरों पर चल रही राजनीतिक गणनाओं का परिणाम है। इसे समझने के लिए केवल घटना को नहीं,उसके पीछे के समीकरणों को भी देखना होगा। बिहार में समीकरण कभी साधारण नहीं होते। सबसे पहले बात आती है जातीय संरचना की,जो बिहार की राजनीति की रीढ़ है। भाजपा लंबे समय से बिहार में अपने आधार को केवल ऊंची जातियों तक सीमित नहीं रखना चाहती थी।

पिछड़ी जातियों,विशेषकर कुर्मी,कोइरी और अन्य ओबीसी समूहों में अपनी पकड़ मजबूत करना उसकी रणनीति का हिस्सा रहा है। इस संदर्भ में सम्राट चौधरी का चयन एक सोचा-समझा कदम है। वे खुद एक प्रभावशाली पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनके माध्यम से भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह सामाजिक प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे नहीं है। यह निर्णय एक तरह से उस राजनीतिक रिक्तता को भरने की कोशिश भी है,जो लंबे समय से क्षेत्रीय दलों के पास रही है।

बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का नेतृत्व लालू यादव और बाद में नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने किया। भाजपा के सामने हमेशा यह चुनौती रही कि वह इस सामाजिक आधार में अपनी जगह कैसे बनाए। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना उसी रणनीति का विस्तार है-एक संकेत कि भाजपा अब केवल 'ऊपर से'नहीं,'नीचे से'भी राजनीति करना चाहती है। यह उल्लेखनीय है कि सम्राट भाजपा में आने के पहले अन्य दलों में भी रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की नहीं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है,जो नेतृत्व को केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं,बल्कि संगठनात्मक संतुलन के आधार पर तय करती है।

सम्राट चौधरी पार्टी में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर काम कर चुके हैं। उनका चयन यह भी दिखाता है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहती है कि संगठन में काम करने वालों को अवसर मिल सकता है। यह आंतरिक अनुशासन और निष्ठा बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। बिहार में सत्ता गठबंधन की राजनीति के तहत चलती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का चयन केवल पार्टी का निर्णय नहीं, बल्कि सहयोगी दलों के साथ संतुलन का भी प्रश्न होता है। सम्राट चौधरी का चेहरा इस संतुलन को कैसे साधेगा? यह भी देखना होगा कि बिहार की राजनीति में गठबंधन जितनी जल्दी बनते हैं,उतनी ही जल्दी टूटते भी हैं।

भाजपा को यह समझ आ गया है कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर बिहार में स्थायी बढ़त बनाना मुश्किल है। यहां स्थानीय नेतृत्व और जातीय समीकरण, दोनों निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सम्राट चौधरी का उभार आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर भी देखा जा सकता है। यह एक तरह से भविष्य के नेतृत्व का संकेत है,जिससे मतदाताओं को एक स्पष्ट चेहरा दिखाया जा सके। हालांकि इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं। बिहार में नेतृत्व को स्वीकार करना केवल जाति या पार्टी के आधार पर नहीं होता,बल्कि वहां एक प्रकार की राजनीतिक विश्वसनीयता भी जरूरी होती है। सम्राट चौधरी को यह साबित करना होगा कि वे केवल एक समीकरण का हिस्सा नहीं,बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी हैं। प्रशासनिक अनुभव, निर्णय लेने की क्षमता और संकट प्रबंधन-ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, जहां उनकी परीक्षा होगी।

विपक्ष सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को भाजपा का एक राजनीतिक प्रयोग कहकर सवाल उठा सकता है, लेकिन इसी के साथ उन्हें अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की जरूरत भी महसूस होगी। इससे बिहार की राजनीति में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से सकारात्मक ही होगा। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय राजनीति का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य भी है। भाजपा विभिन्न राज्यों में अपने नेतृत्व को इस तरह गढ़ रही है, ताकि वह क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एजेंडे के बीच संतुलन बना सके।

सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां पार्टी स्थानीय चेहरों के माध्यम से अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहती है,बिना अपने केंद्रीय नेतृत्व की छवि को कमजोर किए। आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। बिहार लंबे समय से विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से जूझ रहा है।

लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धः पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर

हेमेन्द्र क्षीरसागर
बालाघाट,मध्यप्रदेश

पूर्व प्रधानमन्त्री श्री चंद्रशेखर को याद करते हुए एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत का चेहरा सामने आता हैं। जो बिना राजनीतिक नफा-नुकसान की परवाह किए, देशहित में दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए देश के सामने अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। यारों के यार तो वे थे ही,अपने निजी सरोकारों के निभाने में भी उनका कोई जबाब नहीं था। चंद्रशेखर जी की विपरीत परिस्थितियों में साहसिक निर्णय लेने की परख उस वक्त भी देखने में आई,जब प्रथम खाड़ी युद्ध शुरू हुआ और देश के सामने विदेशी मुद्रा का भारी संकट था। ऐसी विकट परिस्थिति आ गई थी कि जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था।

कठिन समय का मुकाबला

जीवनरक्षक दवाओं के आयात के लिए भी एक हफ्ते का विदेशी मुद्रा शेष था। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा की लगभग वैसी ही स्थिति थी। तब केंद्र में चंद्रशेखर जी की अल्पसंख्यक सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही थी। देश के सामने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तत्कालीन आईएमएफ के चेयरमैन भारत पर कर्ज के एवज में मनमानी शर्तें थोपने पर आमादा थे। यह मानकर कि यह सरकार अल्पसंख्यक है और ज्यादा दिन चलेगी नहीं। आई एम एफ चेयरमैन ने बातचीत के सिलसिले में ही एक बार यहां तक हिदायत दे दिया कि, अगर हम कर्ज देने से मना कर दिए,तब आप क्या करेंगे?

चन्द्रशेखर जी का सीधा जबाब था कि-एक तो शर्तों के मुताबिक आप ऐसा कर नहीं सकते,दूसरा अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं इस मीटिंग से उठकर सीधे आकाशवाणी जाऊंगा और देशवासियों से अपील करूंगा कि आईएमएफ से कर्ज मिलने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। देशवासियों आप आने वाले कठिन समय का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें।

बेबाक जबाब

जब कभी बातचीत के दौरान चंद्रशेखर जी पूछा जाता था कि,देश का सोना गिरवी रखते हुए आपको यह नहीं लगता था कि इससे देश की बदनामी होगी? चंद्रशेखर जी का बेबाक जबाब होता था कि-आखिर अपने घर की बहू-बेटियों के लिए सोने के गहने-जेवरात किस लिए दान दिए जाते हैं? उसके पीछे असली मकसद यहीं होता है कि-किसी विपरीत परिस्थिति में वे अपना गहना-जेवर गिरवी रखकर अपना जीवन निर्वाह करें। महज श्रृंगार के लिए ही गहने-जेवर नहीं होते हैं। यह एक ठेठ गवई मन के सोच का ही नतीजा है। जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चंद्रशेखर जी के पूरे व्यक्तित्व में आजीवन बरकरार रहा।

सामाजिक परिवर्तन की राजनीति

वह हमेशा सत्ता की राजनीति का विरोध करते थे एवं लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को महत्व देते थे।

आपातकाल के दौरान जेल में बिताये समय में उन्होंने हिंदी में एक डायरी लिखी थी जो बाद में 'मेरी जेल डायरी' के नाम से प्रकाशित हुई।'सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता' उनके लेखन का एक प्रसिद्ध संकलन है। देश के लिए अपना सर्वस्व होम करने वाले चन्द्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित इब्राहिमपत्ती गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। चन्द्रशेखर अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित थे। क्रांतिकारी जोश एवं गर्म स्वभाव वाले वाले आदर्शवादी के रूप में जाने जाते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद वे समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्हें आचार्य नरेंद्र देव के साथ बहुत निकट से जुड़े होने का सौभाग्य प्राप्त था। दुःखद 10 नवम्बर,1990 से 21 जून,1991 तक देश के 8 वें प्रधानमंत्री रहे चन्द्रशेखर ने मृत्यु 8 जुलाई, 2007 को अंतिम सांस ली। ऐसे महामना की जयंती पर विनम्र शब्दांजलि!

जब घर ही कब्र बन गया और रिश्ते खामोश गवाह

अपनों के बीच भी अजनबी बनकर दम तोड़ती एक जिंदगी इंसानियत की दरारें: एक मृत्यु जो पूरे समाज पर सवाल छोड़ गई

आर.के.जैन ''अरिजीत''
बड़वानी,मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के नगीन नगर (चंदन नगर थाना क्षेत्र) की तंग गलियों में जब लंबे समय से जमी खामोशी अचानक दरक गई,तो उसके भीतर छिपा भयावह सच पूरे इलाके को भीतर तक हिला गया। एक बंद और उपेक्षित मकान से निकली सड़न और रहस्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सन्न कर दिया। इसी मकान के भीतर 65 वर्षीय वृद्ध का निर्जीव शरीर कुछ दिनों (लगभग दो दिन) से पड़ा हुआ था,और समय के साथ वह उपेक्षा की भयावह तस्वीर बन चुका था। यह घटना केवल मृत्यु की सूचना नहीं थी,बल्कि टूटते रिश्तों,बिखरते परिवार और संवेदनहीन होते समाज का दर्दनाक दर्पण थी। बंद दीवारों के भीतर दबी यह चुप्पी अब एक कठोर प्रश्न बनकर खड़ी है–क्या इस आधुनिक युग में इंसान अपने ही घर के भीतर इतना अकेला और असहाय हो सकता है?

सन्नाटे में दबी हुई सच्चाई जब अचानक सांस लेने लगती है, तो उसका पहला स्पर्श ही पूरे वातावरण को हिला देता है। कॉलोनी के बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे,तभी गेंद अचानक उसी बंद पड़े पुराने मकान के भीतर जा गिरी। गेंद लेने गए बच्चों ने जैसे ही अंदर झांका,तेज दुर्गंध और सड़न की भयावह स्थिति ने उन्हें भयभीत कर दिया। भीतर का दृश्य अत्यंत भयावह था–चूहों द्वारा क्षत-विक्षत शव और मौत का गहरा सन्नाटा। यह सच शायद और भी दिनों तक छिपा रहता, यदि वह गेंद उस बंद मकान में न जाती, जिसने एक अनदेखी और उपेक्षित त्रासदी को उजागर कर दिया।

सूचना मिलते ही चंदन नगर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां भीतर का दृश्य अत्यंत भयावह और दिल दहला देने वाला था–कमरे में फैली सड़ांध,जड़ हो चुकी खामोशी और लंबे समय से उपेक्षित वातावरण यह स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी थी और किसी ने उसकी सुध नहीं ली थी; शव काफी विकृत अवस्था में था, जिससे यह घटना केवल एक पुलिस जांच का विषय न रहकर समाज की संवेदनहीनता और टूटते पारिवारिक संबंधों का कठोर दर्पण बन गई,और सबसे बड़ा प्रश्न यही रह गया कि तीन पुत्रों के होते हुए भी यह व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस तरह पूर्णतः अकेला क्यों रह गया।

जीवन की कठिन धूप में तपकर यह वृद्ध व्यक्ति वर्षों तक मेहनत-मजदूरी करता रहा और अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को कंधों पर ढोता हुआ बच्चों के भविष्य को संवारने में पूरी उम्र खपा दी;अभावों और आर्थिक संघर्षों के बीच भी उसने कभी घर की डोर को टूटने नहीं दिया और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। समय के साथ शराब की लत ने उसके जीवन को अवश्य प्रभावित किया,लेकिन पिता के हृदय में बसे स्नेह और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद कभी कम नहीं हुई,जबकि विडंबना यह रही कि वही बच्चे धीरे-धीरे उससे दूर होते चले गए;त्याग, उपेक्षा और टूटते रिश्तों के बीच यह पवित्र सा बंधन अंततः बिखरकर एक दर्दनाक मौन में बदल गया।

तीन पुत्रों के होते हुए भी यह वृद्ध व्यक्ति अपने अंतिम समय में गहरी एकाकी स्थिति में था; वर्षों से चले आ रहे पारिवारिक मतभेदों ने रिश्तों की नींव कमजोर कर दी थी,जिसके कारण न कोई मुलाकात बची, न कोई हालचाल लेने वाला और न ही कोई जिम्मेदारी निभाने वाला शेष रहा। जिस पिता ने जीवन भर अपनी संतान के भविष्य को संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया,वही अंततः उपेक्षा का शिकार बन गया; कभी स्नेह और अपनत्व से भरे रक्त संबंध धीरे-धीरे दूरी, नाराज़गी और स्वार्थ में बदल गए। यह स्थिति बताती है कि समय के साथ कई रिश्ते भावनाओं से टूटकर केवल औपचारिक औपचारिकता भर रह जाते हैं।

मृत्यु की सूचना मिलने के बाद जब रिश्तेदारों और पुत्रों को खबर दी गई,तो उनका व्यवहार और भी अधिक पीड़ादायक और निराशाजनक था; एक-एक कर सभी ने आने से स्पष्ट इनकार कर दिया,मानो अंतिम संस्कार कोई पारिवारिक दायित्व नहीं बल्कि एक अनचाहा बोझ हो। एक ओर वृद्ध पिता का निर्जीव शरीर पड़ा था,तो दूसरी ओर पुत्रों की संवेदनहीनता और दूरी साफ झलक रही थी। आश्चर्यजनक रूप से संपत्ति को लेकर सक्रियता तो दिखाई दी,लेकिन भावनाओं, कर्तव्य और मानवीय संवेदना का पूर्ण अभाव उजागर हो गया। यह पूरा दृश्य रिश्तों के पतन और सामाजिक मूल्यों के क्षरण की सबसे कठोर और असहज तस्वीर प्रस्तुत करता है।

नगीन नगर,इंदौर की यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं,बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है; आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में मोबाइल,काम और व्यक्तिगत स्वार्थ ने पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट को लगातार कमजोर कर दिया है। बुजुर्ग घरों में अकेलेपन का जीवन जीने को मजबूर हैं, जिनकी देखभाल और हालचाल लेने वाला कोई नहीं बचा। यह घटना उस गहराते सामाजिक संकट को उजागर करती है, जहां इंसान मौजूद होते हुए भी इंसानियत धीरे-धीरे खोती जा रही है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया,तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति और भी भयावह रूप ले सकती है।

क्या 'सम्राट' संभाल पाएंगे नीतीश के भरोसे की विरासत?

योगेश कुमार गोयल
नजफ्फगढ़,नई दिल्ली

चुनौतियों के चक्रव्यूह के बीच खड़ा बिहार का नया 'सम्राट'

बिहार की राजनीति में सत्ता का शिखर छूना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है उस शिखर पर टिके रहकर अपनी सर्वमान्यता सिद्ध करना। सम्राट चौधरी का बिहार के 24 वें मुख्यमंत्री के रूप में उदय राज्य के सियासी इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात माना जा रहा है। यह केवल एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उस 'बड़े भाई' की भूमिका को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना है, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता दशकों से कर रहे थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह नीतीश कुमार की उस लंबी और गहरी छाया से बाहर निकल पाएंगे, जिसने पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति को परिभाषित किया है? यही वह कसौटी है, जिस पर अब सम्राट चौधरी को परखा जाएगा।

सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत,और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष,दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है। राजद और जदयू जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम करने के बाद 2017 में भाजपा का दामन थामना उनके करियर का सबसे निर्णायक मो साबित हुआ। भाजपा ने उनमें एक ऐसे पिछड़ा नेतृत्व (ओबीसी) को देखा, जो न केवल संगठन में जान फूंक सकता था बल्कि राजद के 'माई'(एमवाई) समीकरण के सामने एनडीए के'लव-कुश' समीकरण को मजबूती दे सकता था। विशेषकर कुशवाहा समुदाय से आने के कारण सम्राट चौधरी भाजपा के लिए सामाजिक संतुलन का सबसे सटीक मोहरा साबित हुए। भाजपा ने उन्हें न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद देकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा भी जताया। यही भरोसा आज उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले आया है।

मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति के साथ ही बिहार की राजनीति में एक दुर्लभ संयोग भी जुड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद वह दूसरे ऐसे नेता बने हैं, जिन्होंने पहले उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली और बाद में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यह उपलब्धि उनके कद को तो बे ाती है लेकिन इसके साथ आने वाली अपेक्षाएं उनके लिए हिमालयी

चुनौतियों जैसी हैं। नीतीश कुमार केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वह बिहार के लिए एक 'इंस्टीट्यूशन' बन चुके थे। उनके 20 वर्षों के शासनकाल ने राज्य में सुशासन की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी, जिसमें महिला सुरक्षा, सड़कें, बिजली और शराबबंदी जैसे मुद्दे हर घर से जुड़े थे। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वे स्वयं को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश करते हैं या एक ऐसी नई पहचान गढ़ते हैं, जो नीतीश के 'विकास' और भाजपा की 'वैचारिक प्रखरता' का संगम हो।

अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि नीतीश कुमार जैसा सर्वमान्य नेता बनना सम्राट चौधरी के लिए रातों-रात संभव नहीं होगा। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग, चाहे वह महादलित हो, अति पिछड़ा हो या आधी आबादी (महिलाएं) हो, में गहराई तक थी। सम्राट चौधरी के पास फिलहाल एक मजबूत सांगठनिक ढांचा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है लेकिन उन्हें अपनी 'आक्रामक छवि' को अब 'प्रशासकीय संयम' में बदलना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अब उनके हर फैसले की तुलना नीतीश कुमार के मानकों से की जाएगी। क्या वह उसी सहजता से महादलितों और अति पिछड़ों के हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या वह शराबबंदी जैसी पेचीदा नीतियों को लेकर जनता के बीच अपना स्पष्ट नजरिया रख पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं,जिनका उत्तर उनके कार्यकाल के शुरुआती सौ दिन ही तय करेंगे।

चुनौतियां केवल बाहर ही नहीं, गठबंधन के भीतर भी हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जदयू के भविष्य और निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में प्रवेश ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। जदयू के भीतर इस बदलाव को लेकर एक दबी हुई छटपटाहट है। सम्राट चौधरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन के सहयोगी दल खुद को उपेक्षित महसूस न करें। साथ ही, उन्हें भाजपा के भीतर भी उन वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेना होगा, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पीछे रह गए। सम्राट चौधरी पर उनके पुराने विवादों,जैसे कम उम्र में मंत्री पद से हटाए जाने की घटना और उनके शैक्षणिक पहलुओं को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पेशेवर छवि और शुचिता पर उठने वाले सवालों का सामना उन्हें अपनी कार्यशैली से ही करना होगा।

बिहार में 2025 का जनादेश एक तरह से 'फेयरवेल मैंडेट'जैसा रहा है,जहां जनता बदलाव की मानसिक तैयारी कर चुकी थी। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका ओबीसी समुदाय से होना और भाजपा आलाकमान का पूर्ण समर्थन है लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा 'नीतीश कुमार का औरा' है। भाजपा ने अब तक बिहार में नीतीश कुमार के साये में राजनीति की है, अब उसे अपनी स्वतंत्र इमारत खड़ी करनी है, जिसकी नींव सम्राट चौधरी को रखनी है। यह सफर कांटों भरा है क्योंकि उन्हें न केवल विकास की रफ्तार बनाए रखनी है बल्कि बिहार की उस जटिल सामाजिक संरचना को भी साधे रखना है, जहां जाति की राजनीति कभी खत्म नहीं होती।

महिला आरक्षण को लेकर मायावती का विरोधियों पर तीखा प्रहार

संजय सक्सेना
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले इस कानून ने सभी दलों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया है। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर भाजपा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधी चोट की है। उन्होंने कांग्रेस को गिरगिट तक कह डाला है। मायावती का कहना है कि कांग्रेस दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के मुद्दों पर दोहरा चरित्र अपनाती रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड कभी भरोसेमंद नहीं रहा। मायावती ने आरोप लगाया कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस इन वर्गों की बात कर रही है लेकिन यह महज राजनीतिक मजबूरी है।

मायावती ने अपने पोस्ट में भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए दलितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी करती रही है। समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने पिछड़े वर्गों के प्रति

उदासीन बताया। बसपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण कानून का लाभ एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं को मिलना चाहिए अन्यथा यह कानून मात्र दिखावा साबित होगा। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे इन वर्गों की महिलाओं के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस खबर को गहराई से समझने के लिए हमें पहले महिला आरक्षण अधिनियम के संदर्भ को देखना होगा। यह कानून 128 संशोधन विधेयक के रूप में 2023 में पारित हुआ था। लोकसभा राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इसमें है। लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद होगा जब परिसीमन होगा। इसी बीच मायावती का यह बयान राजनीतिक दलों के बीच आरक्षण के लाभार्थियों को लेकर हो रही बहस को तेज कर रहा है। बसपा हमेशा से दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर निर्भर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण निर्णायक होते हैं वहां यह बयान बसपा की रणनीति का हिस्सा लगता है।

मायावती का कांग्रेस पर गिरगिट कहना कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद आरक्षण नीतियों को लागू तो किया लेकिन कई बार इसे कमजोर करने की कोशिश भी की। उदाहरण के तौर पर 1990 के मंडल आयोग की सिफारिशों के समय कांग्रेस ने विरोध किया था। वी पी सिंह की सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू किया तो कांग्रेस ने इसे अदालत में चुनौती दी। मायावती का इशारा इसी ओर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने से कतरा गई। 2006 में प्रमोशन में आरक्षण बिल लाने की कोशिश हुई लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज जब महिला आरक्षण आया तो कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के कोटे की बात कर रही है जो पहले कभी नहीं उठाई। यह राजनीतिक उलटफेर मायावती को चुभ रहा है।

भाजपा पर मायावती का हमला भी कम तीखा नहीं है। भाजपा ने महिला आरक्षण बिल पास कराया लेकिन इसमें एससी एसटी ओबीसी के उप कोटा का जिक्र नहीं है। विपक्ष ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी। मायावती का कहना है कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर दलितों के खिलाफ अत्याचारों को नजरअंदाज करती है। उत्तर प्रदेश में बसपा शासनकाल में मायावती ने दलितों के लिए कई योजनाएं चलाईं लेकिन अब वे कहती हैं कि भाजपा ने उन सबको उलट दिया। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने चोट की जो यादव और मुस्लिम वोट पर केंद्रित है। सपा को पिछड़ों का ठेकेदार बताते हुए मायावती ने कहा कि यह दल अन्य पिछे ों की अनदेखी करता है।

इस बयान का राजनीतिक संदर्भ गहरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में झटका लगा था। नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद सपा और कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतीं। बसपा मात्र एक सीट पर सिमट गई। अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। मायावती जानती हैं कि महिला आरक्षण बहस में दलित महिलाओं का मुद्दा उठाकर वे अपना वोट बैंक मजबूत कर सकती हैं। बसपा का कोर वोटर जाटव समुदाय है जो एससी का बड़ा हिस्सा है। मायावती का यह पोस्ट दलित युवाओं को लामबंद करने का प्रयास है।

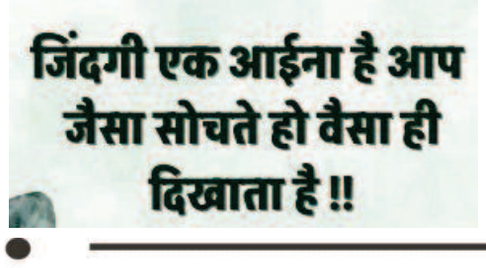

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

CMYK

सरगुजिहा बोलने पर नर्सरी में प्रवेश से इनकार,कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

डीईओ बोले...मामला सही मिला तो कार्रवाई के साथ दिलाएंगे दाखिला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
शहर के चोपड़ापारा स्थित एक निजी स्कूल स्वरंग किड्स एकेडमी के नर्सरी कक्षा में बच्चे को सिर्फ सरगुजिहा बोली बोलने के कारण प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। चोपड़ापारा निवासी राजकुमार यादव अपने साढ़े तीन साल के बेटे का एडमिशन कराने स्वरंग किड्स एकेडमी पहुंचे थे। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने 5-6 दिन तक डेमो क्लास लेने के बाद यह कहकर प्रवेश देने से मना कर दिया कि बच्चा केवल सरगुजिहा बोली में बात करता है और शिक्षक उसे समझ नहीं पा रहे हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि स्कूल प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि अन्य बच्चे हिंदी में बात करते हैं और यदि उनके बेटे को प्रवेश दिया गया तो अन्य बच्चे भी सरगुजिहा बोलना सीख जाएंगे। इस बात से आहत होकर उन्होंने शिकायत दर्ज

कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यदि भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार किया गया है, तो यह गलत है। डीईओ दिनेश झा ने कहा कि शिकायत की जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी और बच्चे का उसी स्कूल में प्रवेश भी सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की बात भी कही।

स्कूल प्रबंधन ने दी सफाई

स्कूल की प्राचार्य नेहा सिंह का कहना है कि बच्चे को समझने और संवाद में दिक्कत हो रही थी। शिक्षक और बच्चा एक-दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे थे,इसलिए अभिभावक को अन्य स्कूल में प्रवेश कराने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया।

एनएसयूआई ने की कार्रवाई की मांग...

शहर के एक निजी प्ले स्कूल में सरगुजिहा भाषा बोलने के कारण 4 वर्षीय बच्चे को प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद एनएसयूआई सरगुजा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार,स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को 6 दिन तक डेमो के लिए बुलाया। इसके बाद यह कहकर प्रवेश देने से मना कर दिया कि बच्चे की सरगुजिहा बोलचाल का अन्य बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले को लेकर परिजनों में नाराजगी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर एनएसयूआई ने जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने स्कूल की मान्यता समाप्त करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बच्चे की भाषा उसकी पहचान है, इसमें कमी नहीं बल्कि स्कूल प्रबंधन की सोच में समस्या है। इस बीच पहल करते हुए बच्चे को बचपन प्ले स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश दिलाया गया। स्कूल संचालक प्रतीक दीक्षित ने कहा कि शिक्षा में भाषाई आधार पर भेदभाव पूरी तरह गलत है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और छात्र नेता मौजूद रहे। मामले को लेकर शहर में चर्चा बनी हुई है।

छात्र-छात्राओं ने विभिन्न थानों का किया भ्रमण,नशे से दूर रहने दी गई समझाइश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले में छात्र-छात्राओं को पुलिस व्यवस्था से परिचित कराने और उनमें जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न थाना व चौकियों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले के कई स्कूलों के बच्चों ने थानों का दौरा कर पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। भ्रमण के दौरान बच्चों को सीसीटीएनएस कक्ष, रोजनामचा, बंदीगृह (हवालात), मालखाना और शस्त्रागार दिखाया गया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आपातकालीन सेवाओं और पुलिस के दैनिक कार्यों की जानकारी सरल भाषा में दी। पुलिस टीम ने छात्र-छात्राओं को गुड टच-बैड टच, पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181, डायल 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के उपयोग की जानकारी भी दी गई।

छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए इससे दूर रहने की सलाह दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध या असहज स्थिति में तुरंत अपने परिजनों और पुलिस को सूचना दें। इस शैक्षणिक भ्रमण से छात्रों के मन में पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक सवाल पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने सरलता से जवाब दिया।

लैब में अव्यवस्था पर फटकार.....

9 कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश

जेडी ने सीएचसी धौरपुर का किया औचक निरीक्षण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अव्यवस्था सामने आने पर जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई गई। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में दवाओं के व्यवस्थित रख-रखाव के निर्देश दिए गए। वहीं लैब में अव्यवस्था पाए जाने पर प्रभारी को चेतावनी देते हुए तत्काल सुधार करने को कहा गया। साथ ही अस्पताल परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए

अस्पताल में कूलर लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करने को कहा गया, ताकि आम लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल सके। उपस्थिति पंजी के निरीक्षण में कई कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। इनमें चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर के 9 कर्मचारी अन्यत्र संलग्न होने के कारण लंबे समय से उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। इस पर संबंधित कर्मचारियों का अप्रैल माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने मैनपाट के मतरिंगा में शेड निर्माण का किया भूमिपूजन

रिहंद नदी उद्गम स्थल को विकसित कर स्थानीय रोजगार सृजन पर जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। इसी क्रम में मैनपाट के मतरिंगा (सितकालो) में शेड निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। मतरिंगा (सितकालो) क्षेत्र रिहंद नदी के उद्गम स्थल के रूप में अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक महत्ता के लिए जाना जाता है। यहां का मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखता है। प्रस्तावित शेड निर्माण से पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुलभ होंगी, जिससे इस स्थल की लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। मंत्री श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सरगुजा क्षेत्र के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करते हुए उन्हें पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है। मैनपाट जैसे रमणीय स्थल को विकसित कर न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार,पर्यटक अनुकूल वातावरण और स्थानीय सहभागिता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इससे न केवल पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रवासियों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

7 करोड़ की लागत से बनने वाले 120 मीटर लंबे पुल का किया भूमि पूजन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अम्बिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़गांवद-पनगोती मार्ग पर स्थित भालू नाला पर पुल निर्माण एवं पहुँच मार्ग के कार्य का आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस पुल की लंबाई 120 मीटर तथा पहुँच मार्ग की लंबाई 362 मीटर होगी। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा और विशेष रूप से बड़गांव, पनगोती सहित आसपास के कई गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक बारिश के मौसम में बाधित रहने वाला यह मार्ग पुल बनने के बाद वर्षभर सुगम और सुरक्षित रहेगा, जिससे स्थानीय जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मंत्री श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होती है,बल्कि शिक्षा,स्वास्थ्य और व्यापार के अवसर भी बढ़ते हैं। अम्बिकापुर के समग्र विकास और क्षेत्रवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ की गई यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस जन-उपयोगी कार्य के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है और उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रदीप सोनी बने प्रदेश उपाध्यक्ष,कई पदों पर नई नियुक्तियां

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ की प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने नई टीम में सरगुजा संभाग को विशेष महत्व दिया है। पूर्व कर्मचारी नेता प्रदीप सोनी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनिल कुमार मिश्रा को प्रदेश मंत्री और अनिल कुमार तिवारी को पशुपालन विभाग प्रकोष्ठ का प्रांतीय संयोजक नियुक्त किया गया है। सीएम सिन्हा को भी प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किया गया है। जशपुर से द्रौपदी यादव को प्रांतीय उपाध्यक्ष और टीपी सिंह को संगठन मंत्री बनाया गया है। कोरिया जिले से डॉ. अरविंद नारायण सिंह को कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है।

361 विद्यार्थियों ने 4 पंचायतों में किया सर्वे,कई हितग्राही अब भी योजनाओं से वंचित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने युवा संवाद कार्यक्रम के तहत गांवों में उतरकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। जिला पंचायत सरगुजा और मुहिम फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस पहल में 361 छात्रों ने चार ग्राम पंचायत-साकालो,मेंड्राखुर्द,कांठी और कर्जी में घर-घर सर्वे किया। छात्रों ने 1167 परिवारों से जानकारी जुटाई। सर्वे में सामने आया कि 89 प्रतिशत परिवारों को महतारी वंदन योजना और 80 प्रतिशत को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। वहीं 82 प्रतिशत विधवा पेंशन और 71 प्रतिशत बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। सर्वे में कई खामियां भी उजागर हुईं। 245 परिवारों के 483 सदस्य आयुष्मान योजना से बाहर हैं। 137 परिवारों के 195 सदस्यों के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़े हैं। 84 बुजुर्ग और 31 विधवाएं अब भी पेंशन से वंचित हैं। इसके अलावा 50 प्रतिशत दिव्यांगों के पास प्रमाण-पत्र नहीं है, जिससे वे योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। करीब 100 परिवारों के आधार कार्ड में सुधार की जरूरत है, जबकि 177 लोगों के पास वोटर आईडी नहीं है। एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग के लगभग आधे परिवारों के पास जाति प्रमाण-पत्र नहीं होने से उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो रही है। जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का प्रयास योजनाओं की 100 प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार होगा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने इसे शिक्षा का वास्तविक स्वरूप बताया।

तालाबों पर अतिक्रमण का मामला गरमाया...प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जल स्रोतों को पाटने पर रोक लगाने की मांग,कलेक्टर ने जांच शुरू होने की कही बात

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
शहर के प्राचीन तालाबों और जल स्रोतों को पाटे जाने के मामलों को लेकर शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल एमआईसी सदस्य मनीष सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी,पार्षद शशिकांत जायसवाल, शिवमंगल सिंह,विपिन पांडेय,कैट मंत्री पंकज गुप्ता और मुकेश गुप्ता भी मौजूद रहे। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के कई क्षेत्रों

में स्थित तालाबों और जल क्षेत्रों को अवैध रूप से पाटकर जमीन में तब्दील किया जा रहा है। खासतौर पर नया बस स्टैंड के सामने स्थित प्राचीन जलाशय में मशीनों से मिट्टी भराई का काम किया जा रहा था,जिसे फिलहाल प्रशासन ने रुकवा दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को किसी भी हाल में नष्ट नहीं किया जा सकता। जिन जलाशयों को पाटा गया है, उन्हें फिर से मूल स्वरूप में लाया जाना चाहिए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 1964 के आसपास संबंधित भूमि का मुआवजा दिया गया था, लेकिन अभिलेखों में त्रुटियों के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं वर्ष 2002 में नगर पालिका परिषद द्वारा यहां घाट निर्माण कराया गया था, जो इस क्षेत्र के जलाशय होने का प्रमाण है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि शहर के सभी तालाबों और जल क्षेत्रों का गूगल मैप के माध्यम से सीमांकन कर अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष टीम गठित की जाए। ज्ञापन मिलने के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेजों में छेड़छाड़ की आशंका है। इसकी जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी तालाबों का सीमांकन कराया जाएगा और जल स्रोतों को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इन स्थानों की जांच की मांग की हैं जिसमें नया बस स्टैंड के सामने स्थित तालाब क्षेत्र,भाठूपारा तालाब, होटल पर्पल आर्किड के पीछे व आसपास, बौरीपारा स्थित रिंग बांध तालाब,ब्रह्मपारा स्थित गढिया,लगभग 1.5 एकड़ शासकीय भूमि शामिल है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाओं के ऑनलाईन संचालन हेतु संभागस्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया को 01 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित करने के लिए सरगुजा संभाग के सभी जिलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला पंचायत सरगुजा के सभा कक्ष में आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय रायपुर के संयुक्त संचालक श्री डी.एस. वर्मा एवं उनके टीम द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की

ऑनलाइन सॉफटवेयर की डिजिटल रूप रेखा की विस्तृत जानकारी दी गई। संयुक्त संचालक श्री डी.एस. वर्मा ने कहा कि विधायक निधि की स्वीकृति एवं राशि जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बाताया कि पिछले एक वर्ष से रायपुर जिले में इस प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा था, अब इसे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। उन्होने सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रक्रिया को बारीकी से समझने कहा ताकि प्रणाली का क्रियान्वयन प्रभावी और सुचारू रूप से किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के सभी जिलों के जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी एवं कर्मचारी, विधायकों के निज सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सभी जिलों के समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों के अधिकारी एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपस्थित थे।

मैनपाट में चला प्रशासन का बुलडोजर,3 अवैध निर्माण ध्वस्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
मैनपाट में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोलर चला। राजस्व भूमि पर लंबे समय से काबिज लोगों का अतिक्रमण हटाया गया। टीम ने दो अवैध मकान व एक गुमटी पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा मैनपाट में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को दो से तीन मकानों को जेसीबी से तोड़वा दिया गया। इसके अलावा एक व्यक्ति अहाता देकर राजस्व भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। जिसे हटाया गया। वहीं एक गुमटी पर भी कार्रवाई की गई है। ये सभी 10 से 15 वर्ष से राजस्व भूमि पर काबिज थे। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कार्रवाई के दौरान हल्का विवाद की स्थिति बनी जिसे पुलिस बल ने नियंत्रण किया। 40 को नोटिस,3 पर कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा 40 घरों को नोटिस दिया गया था।

जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय का मेगा दौरा...सियान गुड़ी,स्पेस ऑन व्हील्स समेत विकास की कई बड़ी सौगातें

जशपुर को मिली विकास की रफ्तार : बुजुर्गों,महिलाओं,किसानों और बच्चों के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ

बुजुर्गों संग कैरम,बच्चों से अंतरिक्ष की बात... जशपुर में सीएम साय का अलग अंदाज

सियान गुड़ी से सम्मान,स्पेस ऑन व्हील्स से विज्ञान... जशपुर में विकास का नया मॉडल

जशपुर में योजनाओं की झड़ी : सियान गुड़ी,ड्रोन दीदी, तरिया अभियान और आवास वितरण की सौगात

जशपुर में सीएम साय का शक्ति प्रदर्शन : एक दिन में कई योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ

- जल,रोजगार और तकनीक पर जोरः जशपुर में 500 तरिया, ड्रोन दीदी और पशुपालन योजनाओं की शुरुआत
- जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मेगा दौराः सियान गुड़ी से स्पेस ऑन व्हील्स तक, विकास, विज्ञान और जनकल्याण की कई बड़ी सौगातें

जशपुरनगर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा विकास,जनसंवाद और जन कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के रूप में ऐतिहासिक साबित हुआ। एक ही दिन में शिक्षा,विज्ञान,महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था,जल संरक्षण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और विस्तार किया गया, जिला मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों और आमजनों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। आदिवासी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हुए जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य से अतिथियों का अभिनंदन किया, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और उल्लास से भर गया।

'सियान गुड़ी' का शुभारंभः बुजुर्गों को मिला सम्मान और संबल- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित 'सियान गुड़ी' डे-केयर सेंटर का लोकार्पण किया, यह केंद्र बुजुर्गों के सर्वांगीण विकास और सम्मानजनक जीवन के उद्देश्य से तैयार किया गया है,कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के साथ कैरम खेलकर उनका हौसला बढ़ाया,वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शतरंज खेलकर आत्मीय संवाद स्थापित किया, मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वरिष्ठजन भावुक और प्रसन्न नजर आए,मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को फूड बास्केट,धार्मिक पुस्तकें,शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया,उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश में जहां एकल परिवार और व्यस्त जीवनशैली के कारण बुजुर्गों को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, वहां 'सियान गुड़ी' जैसे केंद्र उनके लिए नई ऊर्जा और सहारा प्रदान करेंगे,यह केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें योग, प्राणायाम,स्वास्थ्य परीक्षण,टेलीमेडिसिन, मनोरंजन,पुस्तकालय,फिजियोथैरेपी, डिजिटल साक्षरता और कानूनी परामर्श जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक यहां विभिन्न गतिविधियां संचालित होंगी, जिससे बुजुर्गों को सक्रिय और खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

'स्पेस ऑन व्हील्स': जशपुर में विज्ञान की नई उड़ान

मुख्यमंत्री ने रणजीता स्टेडियम में इसरो की 'स्पेस ऑन व्हील्स' मोबाइल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी ने जिले के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति नई जिज्ञासा और उत्साह उत्पन्न किया है,प्रदर्शनी में रॉकेट,उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों से जुड़े मॉडलों को प्रदर्शित किया गया, जिन्हें स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री को सरल भाषा में समझाया,शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं—अंशु पासवान, भूमिका डाहरे और सारिका साहनी—ने चंद्रयान, मंगलयान, पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे मिशनों की कार्यप्रणाली को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, मुख्यमंत्री ने बच्चों के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक समझ की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहलें ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, 'अन्वेषण' कार्यक्रम के तहत आयोजित इस पहल से जिले के 10 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, यह मोबाइल प्रदर्शनी बस 14 दिनों तक विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दे रही है।

पशु सखियों के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन-मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पशु सखियों के लिए बकरी और मुर्गी पालन प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन किया, इस पहल का उद्देश्य पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि करना है,पूर्व में प्रशिक्षण सामग्री के अभाव में पशुपालकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे पशुओं के पोषण,टीकाकरण और रोग पहचान में कठिनाई,अब इस मार्गदर्शिका के माध्यम से पशु सखियां बेहतर तरीके से ग्रामीणों का मार्गदर्शन कर सकेंगी,जिससे उत्पादन में वृद्धि और आय में सुधार होगा।

ड्रोन दीदी योजना : महिलाओं को तकनीक से सशक्त बनाने की पहल- 'लखपति दीदी' पहल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने महिलाओं को ड्रोन और सॉयल टेस्टिंग मशीन प्रदान की। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, सॉयल टेस्टिंग मशीन के माध्यम से अब किसान अपनी भूमि की गुणवत्ता का सटीक विश्लेषण कर सकेंगे, जिससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग संभव होगा, इससे लागत में कमी, उत्पादन में वृद्धि और भूमि की उर्वरता में सुधार होगा,ड्रोन तकनीक के उपयोग से कृषि कार्यों में तेजी और दक्षता आएगी, जिससे महिलाओं के लिए आय के नए अवसर सृजित होंगे।

'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' महाअभियान : जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम-मुख्यमंत्री ने जशपुर में 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' महाअभियान का शुभारंभ करते हुए 500 नए तरिया (तालाब) निर्माण का शिलान्यास किया,यह अभियान जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है,मनरेगा के तहत 10,000 आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 13,000 से अधिक डबरी निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। यह इस अभियान की प्रभावशीलता और जनभागीदारी को दर्शाता है,मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है,इससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, आजीविका डबरी के माध्यम से मत्स्य पालन,सब्जी उत्पादन,वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा,जिससे अतिरिक्त आय के अवसर उत्पन्न होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजनाः हितग्राहियों को मिली सौगात-मुख्यमंत्री ने पीएम जनमन योजना के तहत 5 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान की चाबियां सौंपीं, इनमें विभिन्न विकासखंडों के हितग्राही शामिल हैं, जिन्हें अब पक्का आवास उपलब्ध हो गया है,मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना गरीब और वंचित वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

समग्र विकास की दिशा में मजबूत पहल-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दौरा केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जशपुर जिले के समग्र विकास की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है,एक ओर जहां 'सियान गुड़ी' के माध्यम से बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा मिली, वहीं 'स्पेस ऑन व्हील्स' से बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, महिलाओं को ड्रोन तकनीक और पशुपालन प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाया गया,तो जल संरक्षण अभियान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली।

जनभागीदारी और विकास का संदेश- इस पूरे दौरे के दौरान एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि राज्य सरकार विकास को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखकर उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है,जनभागीदारी,तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से योजनाओं को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जशपुर में आयोजित यह दौरा न केवल विकास कार्यों की समीक्षा और शुभारंभ का अवसर बना,बल्कि यह संदेश भी दिया कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना है।

नागरिकों से कलेक्टर ने किया सहयोग की अपील..स्व-गणना की प्रक्रिया 16 से 30 अप्रैल तक

-संवाददाता-
बलरामपुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई से 30 मई 2026 तक किया जाएगा। इसके पूर्व स्व-गणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित की जा रही है। बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने स्वगणना के माध्यम से स्वयं जनगणना में रजिस्टर किया है। कलेक्टर श्री कटारा ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्व-गणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सही एवं पूर्ण जानकारी दर्ज कर जनगणना कार्य को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने बताया कि नागरिक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल https://se.census.gov.in/ पर जाकर अपने परिवार एवं मकान से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। स्व-गणना के दौरान दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने से पहले संशोधित किया जा सकता है,लेकिन एक बार जानकारी सबमिट होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। स्व-गणना पूर्ण करने वाले प्रत्येक परिवार को एक विशेष स्व-गणना आईडी प्रदान की जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। 01 मई से 30 मई 2026 के बीच जब प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे,तब संबंधित परिवारों को यह आईडी साझा करनी होगी। इसके आधार पर प्रगणक दर्ज जानकारी की पुष्टि कर उसे अंतिम रूप देंगे।

खड़े ट्रक से टकराई यात्री बस,एक की मौत,दर्जनभर घायल

एनएच पर बिना संकेत खड़े ट्रक से आधी रात हादसा,तीन की हालत गंभीर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर गुरुवार आधी रात एक बड़ा सडक़ हादसा हो गया। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के नवापारा में तेज रफ्तार यात्री बस सडक़ किनारे खराब खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में बस के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 11.15 बजे झारखंड से दुर्ग जा रही रॉयल बस 06 जीवाई-0729 तेज रफ्तार में थी। बस में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। इसी दौरान बस सामने बिना किसी चेतावनी संकेत के खड़े ट्रक सीजी 07 सीजे 2971 से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

ग्रामीणों ने संभाली राहत की कमान : हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। टूटे कांच और मुड़े दरवाजों के बीच फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही लटोरी और खडग़वां पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।

इन घायलों का चल रहा इलाज
दुर्घटना में अमृता, सुलेखा (छतरपुर, पलामू),अली जान (बरगढ़),अरविंद, सरताज, हीरोध (कल्याणपुर), हर्ष कुमार, नीलमती,संध्या,गुरु प्रसाद (रामानुजगंज), फलिस्ता (भंडारिया) और विनय पैकरा (गढ़वा) घायल हुए हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में बस कर्मचारी कांकेर निवासी 23 वर्षीय किशोर साहू (पिता रामदयाल साहू) की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था।

एनएच-130 पर भीषण हादसा,बाइक सवार युवक की मौके पर मौत

ट्रक और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत,शव की शिनाख्त नहीं

-संवाददाता-
लखनपुर,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे-130 पर शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक सडक़ हादसा हो गया। कमल फ्यूल के सामने बाइक और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंबिकापुर की ओर से आ रहे ट्रक (क्रमांक सीजी 07 सीएस 7684) ने सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक के सिर में गंभीर चोट आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। युवक का चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे-130 पर लगातार सडक़ हादसे हो रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को हेलमेट पहनने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी जा रही है।

कोरिया में डिजिटल क्रांति की शुरुआत: 14 अटल सुविधा केन्द्रों का लोकार्पण

अब गांव भी होंगे ऑनलाइन,70 लाख से बने डिजिटल सुविधा केन्द्र शुरू

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी सौगात...कोरिया को मिले 14 डिजिटल केन्द्र

- गांव-गांव पहुंचेगी ई-गवर्नेंस,कोरिया में डिजिटल सेवाओं का विस्तार
- सड़क के साथ डिजिटल विकास,कोरिया में दोहरी रफ्तार से बढ़ता विकास
- अब नहीं जाना पड़ेगा शहर,गांव में ही मिलेंगी सभी ऑनलाइन सेवाएं
- ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत,एक ही जगह मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं
- डिजिटल इंडिया की ओर मजबूत कदम,कोरिया में सुविधा केन्द्रों का शुभारंभ
- रोजगार और सुविधा दोनों,कोरिया में खुले 14 अटल डिजिटल केन्द्र

-संवाददाता-
कोरिया,17 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी बहुल इलाकों में विकास की रफ्तार को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरिया जिले को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है,शुक्रवार को जशपुर से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ जिले में निर्मित 14 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का शुभारंभ किया। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और शासन की सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

70 लाख की लागत से तैयार हुए आधुनिक डिजिटल केन्द्र

कोरिया जिले में स्थापित इन 14 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का निर्माण वर्ष 2024-25 की स्वीकृत योजनाओं के तहत लगभग 70 लाख रुपये की लागत से किया गया है, यह सभी केन्द्र अब पूरी तरह से तैयार हैं और ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू कर दिए गए हैं,इन केन्द्रों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सुविधाओं की कमी को दूर किया जा सके। प्रत्येक केन्द्र को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी,कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों,जिससे ग्रामीणों को बिना किसी परेशानी के सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ मिल सके।

बैकुण्ठपुर और सोनहत में केन्द्रों की स्थापना- इन डिजिटल सुविधा केन्द्रों की स्थापना जिले के दो प्रमुख जनपद पंचायतों–बैकुण्ठपुर और सोनहत–में की गई है, बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में केन्द्र स्थापित किए गए हैं,उनमें जमगहना,नगर,सलबा,मुरमा,मनसुख,तेन्दुआ और डुमरिया शामिल हैं,वहीं सोनहत जनपद पंचायत के अंतर्गत अकलासरई,पुसला, सोनहत,कुशहा,सुन्दरपुर,रामगढ़ और आनंदपुर ग्राम पंचायतों में ये केन्द्र स्थापित किए गए हैं, इन केन्द्रों के माध्यम से दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अब डिजिटल सेवाओं के लिए शहरों या तहसील मुख्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

ग्रामीणों को मिलेंगी एक ही छत के नीचे कई सेवाएं- अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को अब विभिन्न प्रकार की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इनमें प्रमुख रूप से जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन,विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया,डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाएं, पेंशन,राशन और मनरेगा से संबंधित जानकारी,ई-गवर्नेंस सेवाओं की उपलब्धता, अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम- इन केन्द्रों का शुभारंभ केवल सेवाओं की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से ग्रामीणों को तकनीक के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, इससे वे न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे,बल्कि ऑनलाइन शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसरों से भी जुड़ सकेंगे,विशेष रूप से युवाओं के लिए यह केन्द्र अवसरों के नए द्वार खोलेंगे, स्थानीय स्तर पर इन केन्द्रों के संचालन के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होगी,जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

सड़क और डिजिटल सुविधा: विकास के दो मजबूत पहिए- मुख्यमंत्री द्वारा एक ही मंच से सड़कों के लोकार्पण और डिजिटल केन्द्रों के शुभारंभ को विकास के दो महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखा जा रहा है, एक ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है,जिससे आवागमन आसान हो रहा है,वहीं दूसरी ओर डिजिटल सुविधा केन्द्रों के माध्यम से गांवों को तकनीकी रूप से जोड़ा जा रहा है, यह दोहरा विकास मॉडल ग्रामीण जीवन को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डिजिटल इंडिया के सपने को मिल रही मजबूती- भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल का मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है,कोरिया जिले में स्थापित ये केन्द्र इस लक्ष्य को जमीनी स्तर पर साकार करने का कार्य करेंगे,अब गांवों में रहने वाला व्यक्ति भी शहरों की तरह ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की डिजिटल खाई कम होगी।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सराहनीय पहल- इस परियोजना को सफल बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, योजनाओं का सही क्रियान्वयन और समय पर कार्य पूर्ण करना इस बात का संकेत है कि जिले में विकास कार्यों को गंभीरता से लिया जा रहा है,स्थानीय स्तर पर भी लोगों में इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि यह केन्द्र उनके जीवन को आसान बनाने में मदद करेंगे।

भविष्य में और विस्तार की संभावना- अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों की सफलता को देखते हुए भविष्य में इनका और विस्तार किया जा सकता है,जिले के अन्य ग्राम पंचायतों में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई जा सकती है,जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें,इसके साथ ही इन केन्द्रों में नई-नई सेवाओं को जोड़कर इन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल- कोरिया जिले में 14 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का शुभारंभ ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है,यह न केवल डिजिटल सेवाओं की पहुंच को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी मदद करेगा, इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क और डिजिटल सुविधा जैसे दो मजबूत स्तंभों के सहारे कोरिया जिला अब तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, आने वाले समय में यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है,जहां विकास और तकनीक का संतुलित समावेश ग्रामीण जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

क्षमता विकास और ग्राम स्वराज अभियान का मिला सहयोग-

इन अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों के निर्माण में विभिन्न योजनाओं का समन्वय किया गया है, अधिकांश केन्द्र 'क्षमता विकास योजना' के तहत बनाए गए हैं, जबकि कुछ केन्द्रों का निर्माण 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के अंतर्गत किया गया है, इस समन्वित प्रयास से यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का यह उदाहरण प्रशासनिक दक्षता को भी दर्शाता है।

महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा विशेष लाभ-

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर महिलाएं और बुजुर्ग तकनीकी सेवाओं से दूर रह जाते हैं, अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र इस दूरी को कम करने का काम करेंगे, महिलाएं अब स्वयं अपने दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगी और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, वहीं बुजुर्गों को पेंशन और अन्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, यह पहल सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देगी, जहां हर वर्ग को समान रूप से लाभ मिलेगा।

गुरुकुल स्कूल के बच्चों ने किया थाना लखनपुर का भ्रमण

-संवाददाता-
लखनपुर, 17 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

गुरुकुल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने आज सुबह नगर पंचायत लखनपुर के थाना का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस भ्रमण में स्कूल के शिक्षक भी बच्चों के साथ उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी ने बच्चों को पुलिस कार्यप्रणाली, थाने के विभिन्न विभागों तथा कानून व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। बच्चों को गुड टच-बैड टच, साइबर क्राइम, सी.सी.टी.एन.एस. और यातायात नियमों की भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद बच्चों ने थाना प्रभारी से विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सहजता से उत्तर दिया। भ्रमण समाप्त होने के बाद बच्चों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल देखा गया। थाना प्रभारी संतोष पोटाई, पिताम्बर सिंह, अमित गुप्ता तथा दशरथ राजवाड़े सहित अन्य स्टाफ इस अवसर पर उपस्थित रहे।

निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से युवक की मौत

-संवाददाता-
कोरबा,17 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के काशी नगर बुधवारी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां निर्माणाधीन मकान में काम करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान दादर बस्ती निवासी टीकाराम यादव (28) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, वह दो मंजिला मकान में सरिया बिछाने का काम कर रहा था। इसी दौरान सरिया ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और वह छत से नीचे गिर गया। घटना के बाद साथियों ने उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, टीकाराम परिवार का सबसे छोटा और कमाने वाला सदस्य था। उसने घर की जिम्मेदारियों के चलते शादी भी नहीं की थी। उसकी अचानक मौत से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विष्णु पाल आ0 लाल बिहारी, निवासी ब्रम्हपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम हंसुली स्थित भूमि खसरा नंबर 25/10 रकबा 0.304 हे0 भूमि आवेदक की भूमि है, किन्तु वर्तमान में उक्त भूमि के अलावा खसरा नंबर 25/2 रकबा 0.304 हे0 भूमि अतिरिक्त दर्ज हो गया है। आवेदक द्वारा खसरा नंबर 25/2 रकबा 0.304 हे0 भूमि को विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06/05/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 10/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-02

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 /अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामा आ. रामलगन महतो, निवासी ग्राम बण्डाबहरा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 4672/1, 4761 रकबा क्रमशः 0.362, 0.063 हे. भूमि में से आवेदक का 1/3 हिस्सा कब्जा, किस्म और कीमत के आधार पर * पृथक किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 18/05/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 16/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 /अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आलम पिता देवान, निवासी ग्राम माझापारा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम माझापारा स्थित खसरा नंबर 123/1, 124/1, 376/2, 389/1, 396/1, 691/1, 727/1 रकबा क्रमशः 0.227, 0.049, 0.074, 0.078, 0.040, 0.042, 0.096 हे. भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/2 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 18/05/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 16/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार दरिमा जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णागोपाल आ0 बाघराम वगै0 निवासी ग्राम पम्पापुर तहसील दरिमा जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पम्पापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1/38 रकबा 0.591 हे. भूमि को अनावेदक अमर कुमार आ0 स्व. भगतराम जाति गोड़ निवासी बोझा तहसील प्रतापपुर को विक्रय करने का सौदा किया गया है। जो अनुमति हेतु आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो उचित जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आक्षेप/दावा हो अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अभिभावक /अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29/04/ 2026 को उपस्थित होकर पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

सील — तहसीलदार दरिमा,जिला-सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ममता सिन्हा आ0 प्रभात कुमार सिन्हा जाति, निवासी सरस्वती निवास, मोहल्ला केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला सत्तीपारा, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 831/8 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 28-04-2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 13/04/26 मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

मनोज साहू बने 'मन की बात' कार्यक्रम के जिला संयोजक

-संवाददाता-
कोरिया,17 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी, जिला-कोरिया द्वारा संगठनात्मक नियुक्ति करते हुए मनोज साहू को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है,यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है,मनोज साहू लंबे समय से संगठन के प्रति सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, उनकी कार्यशैली,लगन और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग का प्रावधान हेतु निविदा सूचना

क्र.सं. (1) ई-निविदा सूचना संख्याः 81A-एसटी-टेंडर-2025 दिनांक- 10.04.2026
कार्यः "बिलासपुर डिवीजन के अनूपपुर-बोरीडांड खंड और मौहारी-छुलहा बाईपास लाइन के लिए डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग का प्रावधान"।
निविदा मूल्यः ₹ 5,18,31,891.94/- (रुपये पाँच करोड़ अठारह लाख इकतीस हजार आठ सौ इक्यानबे और चौरानबे पैसे मात्र)।
अमानत राशिः ₹ 10,36,600/- (दस लाख छत्तीस हज़ार छः सौ रूपये मात्र)। **निविदा का जमा होना : दिनांक – 04.05.2026 के 15:00 बजे तक।**
उपरोक्त ई-निविदा सूचना की पूरी जानकारी **https://www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदा हेतु ई-टेंडर के अलावा अन्य टेंडर स्वीकार नहीं की जाएगी।
मंडल संकेत एवं दूर. इंजी./CIC सीपीआर/10/41 द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर
South East Central Railway @secrail

RO No.121484 D.17/04/2026

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, (E&M) DIVISION PUBLIC HEALTH ENGG.DEPTT. AMBIKAPUR (C.G.)

No. 489/2026-27/TS/E.E./E&M/Dn./P.H.E.D./Ambikapur Date 16.04.2026

Notice Inviting Tender NIT No. 01/2026-27

Sealed tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh on Form "C" for Supply work carried out as mentioned below from the manufacturer or their authorized dealers having experience to do such type of work.

S.NO	Brief Description of Materials	Qty.
01	Supply of 6" dia (142 mm) valveless / digger type or equivalent Hammer suitable for 150 mm dia tube well drilling by 275 PSI capacity hydraulically operated rigs.	12 nos

Note:-
01. Cost of Tender From -750-00
02. Estimated Cost (In Rs.):- 881000.00
03. Earnest Money (In Rs.):- 9000.00
04. Bid Submission Date :- 20/04/2026 to 05/05/2026
05. Terms of tender and details of material can be seen in the office during office hours.
06. Conditional tender will not be accepted.

Executive Engineer(E/M) DnResources
Public Health Engineering Department
Ambikapur (C.G.)

जी नंबर-262700237/3

कार्यालय कलेक्टर,बलरामपुर-रामानुजगंज,
मुख्यालय बलरामपुर (छ0ग0)

Phone No-9753356578, Fax No-273004,
Email id collectorbalrampur@gmail.com

निविदा सूचना

क्रमांक-1786/GENS/176-49/2026 SECTION SENIOR CLEARK बलरामपुर,दिनांक 30/03/2026

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छ.ग. के समस्त शासकीय विभाग के अंतर्गत कार्यालयीन उपयोग हेतु वर्ष 2026-27 के लिये स्टेशनरी,लेखन सामग्री से संबंधित निविदा दिनांक 21.04.2026 को दोपहर 3:00 बजे तक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है तथा उसी दिन प्राप्त निविदायें सायं 04.00 बजे निविदाकारों के समक्ष निविदा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी हेतु निविदा की प्रति जिला कार्यालय के सूचना पटल / वेबसाईट https:// Balrampur.nic.in पर देखी जा सकती है।

Digitally signed by Rameshwar Nath Pandey
Date: 30-03-2026 15:12

अपर कलेक्टर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
(छत्तीसगढ)

जी नंबर-252700209/2

नाम सुधार सूचना

मैं चमन सिंह, आ. बिगन सिंह उम्र 29 वर्ष, निवासी दरींडांड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा, छ0ग0 । यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार सत्य एवं सही है। मेरे पुत्र का नाम आयुष कुमार सिंह (AYUSH KUMAR SINGH) है, जो सत्य एवं सही है उक्त नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि प्रपत्रो में दर्ज है।

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम राजवीर कुमार सिंह (RAJVEER KUMAR SINGH) दर्ज है, जबकी मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आयुष कुमार सिंह (AYUSH KUMAR SINGH) है जो सत्य एवं सही है । जिसे मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज कराना चाहता हूं जिस हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत है।

सपथकर्ता
चमन सिंह
निवासी-दरींडांड,अम्बिकापुर
जिला- सरगुजा, छ0ग0

हसदो की सिसकियाँ और मिटता वजूद...कंक्रीट के चमकते शहरों के नाम एक रूहानी वसीयत

अमृतधारा का और गौर घाट का भविष्य संकट में: क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सूखी नदी विरासत में देंगे?

▸▸ हसदो कॉरिडोर बनाने की मांग हुई तेज,नर्मदा नदी की तर्ज पर हसदो किनारे हो वृहद वृक्षारोपण

▸▸ हसदो किनारे नो कंस्ट्रक्शन जोन और ट्री ट्रांसप्लांट जोन घोषित करने की मांग

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

पंद्रह से बीस साल पहले की वो सुबह याद कीजिए, जब कटगोड़ी से दामुज तर्रा से बसेर के साथ अकलासरई से सोनहत के रास्तों पर सूरज की किरणें जमीन तलाशती थीं,जंगल इतने घने थे कि अकेले गुजरने में डर लगता था। आज डर तो नहीं लगता, पर टीस जरूर उठती है, आज उसी स्थान पर खड़े हो जाइए तो नजरें जंगल के पार चली जाती हैं,पेड़ नहीं बचे,बस खालीपन बचा है, अकलासराई से तर्रा और बसेर के बीच जहां से हलफली नदी जन्म लेती है,वहां कभी साल भर पानी का संगीत गूंजता था। आज विकास की ऐसी अंधी दौड़ चली कि नवंबर आते-आते यह नदी एक सूखे नाले में तब्दील हो जाती है।

हर दिन हो रही है 100 'भविष्य' की हत्याएं

सुबह 9 बजे अगर आप इन रास्तों पर निकलें, तो दर्जनों लोग सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लादे दिख जाएंगे,यह सिर्फ लकड़ी नहीं है,यह हसदो के आंचल से छीने गए वे पौधे हैं जिन्हें वृक्ष बनना था।

आंकड़ों का गणित खौफनाक है...

अगर 10 लोग भी रोज निकल रहे हैं,तो हम प्रतिदिन 100 पौधों की हत्या देख रहे हैं,साल भर में हजारों पेड़ धराशायी हो रहे हैं,ऊपर से कोयले की चाहत में मशीनें तर्रा बीट की छाती को छलनी कर रही हैं। यह अंधाधुंध ड्रिलिंग जल स्तर को पाताल में ले जा रही है।

उधार की सांसों पर टिकी है हसदो

विडंबना देखिए,जिस अमृतधारा महोत्सव को हम अपनी पहचान बताते हैं, उसकी मूल नदी हसदो आज खुद अपनी सांसों के लिए तड़प रही है, वर्तमान में हसदो का अस्तित्व बनिया नदी के दिए 'उधार के जल' पर टिका है, गौरघाट के वो पक्षी, वो पेड़ों की छांव अब केवल स्मृतियों में शेष हैं, मेण्ड्रा की पहाड़ियों से निकलने वाली हसदो ने कोरबा की प्यास बुझाई, वहां बिजली पैदा की, जांजगीर और रायगढ़ के खेतों को हरा-भरा किया, लेकिन अपने उद्गम स्थल कोरिया में वह आज 'अनाथ' सी खड़ी है।

अब नही जागे तो हो जाएगी देर

चिरमिरी की प्यास बुझाने वाली हसदो आज खुद प्यासी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सरकार समय चले लोक सुराज अभियान में क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री जनदर्शन में गुहार लगाकर एक इस मांग की शुरुवात किया था पर अफसोस उस समय लोगो ने इसकी गम्भीरता को नही समझा, दरअसल हसदो हमसे कुछ मांग नहीं रही, वह बस अपना खोया हुआ श्रृंगार (जंगल) वापस चाहती है।

कभी ठंडे मौसम के लिए जाना जाता था सोनहत क्षेत्र अब यहां भी गर्मी की मार

सोनहत की वह ठंडी तासीर अब बीते दौर की बात हो गई है, कभी जिस इलाके में गर्मियों के दिनों में भी शाम ढलते ही चादर ओढ़नी पड़ती थी, आज वहां सूरज की तपिश झुलसाने लगी है, घने जंगलों के कटने और हसदो की धारा सूखने का सीधा असर यहां के सूक्ष्म-जलवायु पर पड़ा है, आंकड़ों की बात न भी करें, तो स्थानीय अनुभव बताते हैं कि बीते दो दशकों में औसत तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है,उसने सोनहत की पहचान 'कोरिया के शिमला' वाली छवि को लील लिया है। कंक्रीट के बढ़ते जाल और नग्न होती पहाड़ियों ने इस शांत वादी को 'हीट आइलैंड' में तब्दील करना शुरू कर दिया है।

एक संदेश प्रशासन के नाम-

हसदो को सिर्फ एक जल स्रोत मत समझिए, यह हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है, नर्मदा की तर्ज पर हसदो के किनारों को भी हरा-भरा कीजिए,इससे पहले कि 'अमृतधारा' सिर्फ एक नाम रह जाए और इसकी धारा सूख जाए।

प्रशासन और समाज से कुछ चुभते सवाल

हसदो की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए आज हर संवेदनशील नागरिक के मन में कुछ सवाल कौंध रहे हैं,क्या नर्मदा की तर्ज पर हसदो का पुनरुद्धार संभव नहीं? जब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारों पर व्यापक पौधरोपण का अभियान चल सकता है,तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा दायिनी हसदो के लिए ऐसी कोई योजना क्यों नहीं? क्या प्रशासन हसदो और हलफली के किनारों को फिर से हरा-भरा करने का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर सकता,कहां है हमारी जन-भागीदारी? क्या हम सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? क्या सोनहत और कोरिया का हर नागरिक अपनी इस नदी को बचाने के लिए एक 'जन-आंदोलन' खड़ा नहीं कर सकता? स्थानीय जिला प्रशासन और वन विभाग क्या हसदो को बचाने का सामूहिक संकल्प ले सकते हैं? विभागीय चुप्पी का अर्थ क्या है? पेड़ों की कटाई और अवैध रेत उत्खनन ने नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया है, क्या वन विभाग और प्रशासन एक व्यापक अभियान चलाकर इन खाली हो चुके जंगलों में फलदार और छायादार वृक्ष नहीं लगा सकते?

तापमान में बदलाव का दिखने लगा असर

एक पेड़ का कटना केवल लकड़ी का नुकसान नहीं,बल्कि एक प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट की तालाबंदी है,वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक पूर्ण विकसित पेड़ साल भर में इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि दो वयस्क मनुष्य जीवित रह सकें,जब सोनहत के जंगलों में एक पेड़ गिरता है,तो हम प्रतिदिन औसतन 700 से 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता खो देते हैं,इतना ही नहीं,एक अकेला पेड़ अपनी वाष्पीकरण प्रक्रिया से 10 एयर कंडीशनर के बराबर ठंडक पैदा करता है; इसके कटते ही आसपास के स्थानीय तापमान में 2°C से 5°C तक की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। यानी हर गिरता पेड़ हमारे फेफड़ों से हवा और हमारे भविष्य से ठंडक छीन रहा है। '

ग्रीन हसदो कॉरिडोर का बने कॉन्सेप्ट-

हसदेव नदी के संरक्षण की दिशा में 'हसदो कॉरिडोर' का विचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है,इस प्रस्ताव के तहत हसदेव नदी के उद्गम स्थल से लेकर अमृतधारा जलप्रपात तक, नदी के दोनों किनारों पर 500 मीटर के दायरे को 'नो-कंस्ट्रक्शन जोन' (निर्माण निषिद्ध क्षेत्र) और 'ट्री-प्लांटेशन जोन' (वृक्षारोपण क्षेत्र) घोषित करने की मांग की गई है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल नदी के प्राकृतिक प्रवाह को अतिक्रमण से बचाना है,बल्कि व्यापक स्तर पर सघन वृक्षारोपण के माध्यम से स्थानीय जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना भी है,यदि यह कॉरिडोर धरातल पर उतरता है, तो यह जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक 'ग्रीन मॉडल' साबित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जीवनदायिनी नदी को सुरक्षित रखेगा।

सरकार और कम्पनियों के मुनाफे की महंगी कीमत चुका रही हसदो

कोयले की कालिख से रोशन होने वाले शहरों को शायद खबर नहीं कि उस रोशनी की कीमत हसदो अपने अस्तित्व को मिटाकर चुका रही है। हम विकास की उस दहलीज पर खड़े हैं जहाँ हमारे पास 'एसी' तो होंगे, पर पीने को पानी और सांस लेने को शुद्ध हवा नहीं होगी, हसदो की सिसकियां दरअसल हमारी आने वाली पीढ़ियों का विलाप है। फैसला हमें करना है— मुनाफा या जीवन? '

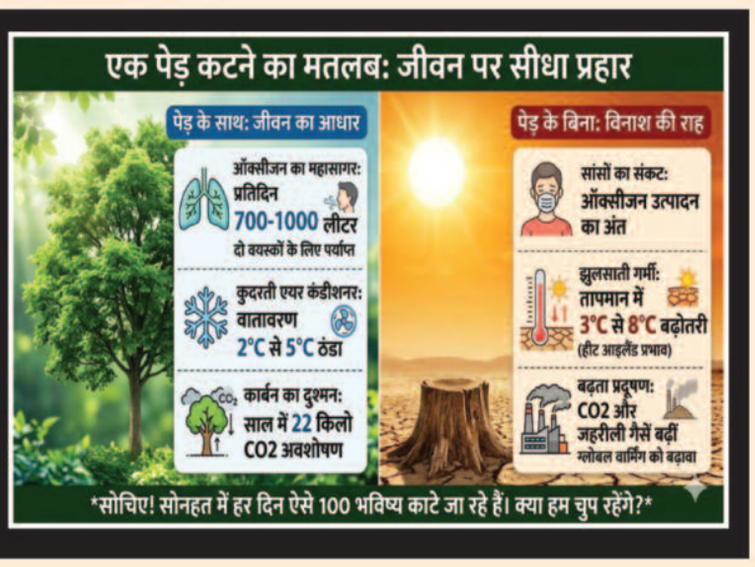

सीबीएसई 10वीं परिणाम : डीएवी पब्लिक स्कूल पांडोपारा में उत्कृष्ट प्रदर्शन,अनमोल विश्वकर्मा 97.20% के साथ टॉपर

-संवाददाता-
कोरिया/पटना,17 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही डीएवी पब्लिक स्कूल पांडोपारा में खुशी की लहर दौड़ गई,इस वर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ का परिचय दिया। खासतौर पर कई छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

अनमोल विश्वकर्मा ने किया टॉप- विद्यालय के छात्र अनमोल विश्वकर्मा ने 97.20 प्रतिशत अंक अर्जित कर प्रथम स्थान हासिल किया, अनमोल, कटकोना एसईसीएल में माइनिंग मैनेजर के पद पर पदस्थ कृष्ण कुमार विश्वकर्मा के पुत्र हैं, शुरू से ही मेधावी रहे अनमोल ने निरंतर मेहनत, अनुशासन और एकाग्रता के बल पर यह मुकाम हासिल किया।

परिवार और शिक्षकों को दिया श्रेय- अपनी इस सफलता पर अनमोल ने कहा कि वह इसका पूरा श्रेय अपने माता-पिता और विद्यालय के शिक्षकों को देते हैं, उनके मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन ने ही उन्हें इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की, अनमोल ने बताया कि नियमित पढ़ाई और समय प्रबंधन उसकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रही।

द्वितीय और तृतीय स्थान पर भी शानदार प्रदर्शन- शौर्य देव आरसे ने 96.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल किया, उन्होंने संस्कृत विषय में 100 में 100 अंक लाकर विशेष उपलब्धि दर्ज की, वहीं अर्थ रंजन सिंह ने 95.60 प्रतिशत अंक अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया और विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

अन्य मेधावी विद्यार्थियों ने भी दिखाया दम- विद्यालय के अन्य प्रतिभाशाली छात्रों में शुभम कुमार (93.40),फाकेला नूर (93.20),प्रीति देवी (93),रेहान रजा (92.8),विश्वजीत मंडल (92.6),श्रेयस कुमार मिश्रा (92.2),ईशान पांडेय (91.8), अथर्व प्रताप सिंह (91),वैष्णवी कुमारी (90.2) और श्रेयांश दुबे (90) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन सभी छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से बेहतर अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम ऊंचा किया।

विद्यालय में जश्न जैसा माहौल- परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्र-छात्राओं के साथ-साथ अभिभावक और शिक्षक भी इस उपलब्धि से गदगद नजर आए, सभी ने एक-दूसरे को बधाई देते हुए इस सफलता का जश्न मनाया।

प्रबंधन ने जताई खुशी- विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम छात्रों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का प्रतिफल है, प्रबंधन ने भविष्य में भी ऐसे ही उत्कृष्ट परिणाम की उम्मीद जताई है।

CMYK

जन नायकन के बाद रजनीकांत की फिल्म पर लगा ग्रहण,मेकर्स ने दे डाली ये चेतावनी

थलापति विजय की जन नायकन लीक होने के बाद अब रजनीकांत की जेलर 2 भी पाइरेसी का शिकार हो गई है।

थलापति विजय-स्टारर फिल्म जन नायकन के ऑनलाइन लीक होने के कुछ ही दिनों बाद, नेल्सन दिलीप कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 के साथ भी ऐसी ही एक समस्या सामने आई है। रजनीकांत की यह फिल्म भी पाइरेसी का शिकार हो गई है। फिल्म का एक वीडियो क्लिप ऑनलाइन सामने आया है, जिसके बाद प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स ने एक सख्त चेतावनी जारी की है।

मेकर्स ने दी सख्त चेतावनी

रजनीकांत की जेलर 2 का यह बीटीसी (बिहाइंड द सीन्स) क्लिप,जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे सेट पर ही शूट किया गया था,सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गया। फैन्स समेत कई लोगों ने इस क्लिप को हटाए जाने से पहले ही शेयर कर दिया था। इसके बाद सन पिक्चर्स ने इस पर बात करते हुए कहा,डियल ऑल,हम आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि जेलर 2 के सेट से लिया गया एक वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो रहा है।

सन पिक्चर्स ने पुष्टि की है कि फिल्म की एंटी-पायरेसी टीम इन क्लिप्स को हटाने और इन्हें शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी एंटी-पायरेसी टीम स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रही है और ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी, जिसमें इन क्लिप्स को शेयर करने या बढ़ावा देने में शामिल अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने फैंस से इस तरह की वीडियो को पोस्ट और शेयर ना करने की रिक्वेस्ट की है।

जन नायकन हुई पाइरेसी का शिकार

इससे पहले, रिलीज के लिए इंतजार कर रही विजय की जन नायकन का एक एचडी प्रिंट ऑनलाइन लीक हो गया था और एक्स (पहले ट्वीटर, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर तेजी से फैल गया था। चेन्नई पुलिस ने इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

जेलर 2 के बारे में

नेल्सन द्वारा निर्देशित जेलर 2 उनकी 2023 की हिट फिल्म जेलर का सीक्वल है। रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन की भूमिका निभाएंगे,जबकि रम्या कृष्णन उनकी पत्नी विजया का किरदार निभाएंगी। फिल्म में शिवा राजकुमार,मोहनलाल भी नजर आएंगे। वहीं मिथुन चक्रवर्ती एक अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है।

अभिनेताओं के हाथों में देश नहीं...

प्रकाश राज ने एक्टर विजय पर कसा तंज?

जन नायकन लीक होने के बीच आया बयान

अभिनेता प्रकाश राज ने अभिनेताओं के पॉलिटिक्स में आने की आलोचना करते हुए इसे राजनीति का सिनेमा मॉडल करार दिया। विजय की फिल्म जन नायकन के को-स्टार प्रकाश राज ने थलापति विजय के राजनीति में आने के बीच अभिनेताओं के पॉलिटिक्स में आने पर तंज कसा है। विजय अपनी पार्टी, तमिलगा वेट्री कजगम के साथ तमिलनाडु के आगामी चुनावों में अपने राजनीतिक डेब्यू से पहले जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं; ऐसे समय में प्रकाश राज ने राजनीति के उस तरीके पर निशाना साधा, जिसे उन्होंने सिनेमा मॉडल कहा।

विजय की सिनेमा मॉडल वाली राजनीति पर प्रकाश राज का तंज

पलानी में सीपीआई के उम्मीदवार एन. पांडी के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, प्रकाश राज ने राज्य में प्रचलित तीन राजनीतिक दृष्टिकोणों का जिक्र किया द्रविड़ मॉडल,गुलाम मॉडलऔर सिनेमा मॉडल। अभिनेता ने फिल्मी सितारों के राजनीति में आने के बढ़ते चलन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जहां अभिनेता परदे पर अलग-अलग तरह की भूमिकाएं बड़ी

ही सहजता से निभा सकते हैं,वहीं असल जिंदगी की राजनीति में एक अलग तरह की जवाबदारी की जरूरत होती है। प्रकाश राज ने कहा, फिल्म में आप डॉक्टर, इंजीनियर या यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन, राजनीति में आप सीधे मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? क्या आपने मेरी तरह राजनीति पर बात की है? क्या आप लोगों और तमिलनाडु के साथ तब खड़े हुए, जब वे मुश्किलों का सामना कर रहे थे? क्या आप भाषा या उसके आत्म-सम्मान के लिए खड़े हुए? लोगों का आपके प्रति जो प्यार है, वह आपकी प्रतिभा के लिए है, न कि आपकी राजनीति के लिए। आप उसी प्यार का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर सकते हैं।

राजनीति और सिनेमा अलग हैं: प्रकाश राज

प्रकाश राज ने आगे कहा कि राजनीति लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत पर ध्यान दें। इसके बजाय, उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा व्यवस्था में अक्सर सत्ता में बैठे लोग राजनीति करते हैं, जबकि आम नागरिकों को असली काम का बोझ उठाना पड़ता है।

प्रकाश राज और विजय का वर्कफंट

राजनीतिक सोच में अंतर होने के बावजूद, प्रकाश राज और विजय का एक लंबा प्रोफेशनल रिश्ता रहा है; उन्होंने घिल्ली, शिवकाशी, विल्लू और आथी जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। उन्हें आखिरी बार फिल्म वारिसु में साथ देखा गया था। ये दोनों एक्टर जल्द ही आने वाली फिल्म जन नायकन में भी साथ नजर आने वाले हैं। हालांकि फिल्म की रिलीज को लेकर थोड़ी गहमागहमी बनी हुई है लेकिन फैंस फिल्म का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

बच्चा पैदा किया है,पहाड़ नहीं खाया...पैपराजी पर भड़की पत्रलेखा,बॉडी शेमिंग पर दिया करार जवाब

अभिनेत्री पत्रलेखा ने हाल ही में मां बनने के बाद बढ़े हुए वजन के कारण बॉडी शेमिंग का सामना किया। अपनी फिल्म %टोस्टर% के प्रमोशन के दौरान मुंबई में पैपराजी द्वारा किए गए कमेंट्स पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। अभिनेता राजकुमार राव की पत्नी और अभिनेत्री पत्रलेखा ने हाल ही में प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा है। पत्रलेखा ने कैम्पा फिल्म्स के बैनर तले टोस्टर फिल्म का निर्माण किया है। मूवी के प्रमोशन के दौरान हाल ही में उन्हें मुंबई में एक्सेल एंटरटेनमेंट के कार्यालय में देखा गया। जहां पत्रलेखा का वजन काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। इस दौरान एक्ट्रेस को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा।

पत्रलेखा ने लगाई पैप्स को फटकार

पत्रलेखा ने हाल ही में नवबंर 2025 में एक बेटी को जन्म दिया है और उसके पांच महीने बाद ही वह बढ़े हुए वजन के साथ नजर आईं। पत्रलेखा के बढ़े वजन और बॉडी पर कुछ पैप पेजेस ने अजीब कमेंट्स किए, जिस पर एक्ट्रेस नाराज हो गईं और खूब सुनाया। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा- पैप पेजेस! मुझे क्या हो गया है? बात ये है कि मैंने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है। हां,मेरा वजन बढ़ गया है,जो आप सबको अजीब लग रहा होगा। मैंने कोई पहाड़ नहीं खाया है। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और साथ ही दो फिल्में प्रोड्यूस की हैं,जो आसान काम नहीं है।पत्रलेखा ने आगे लिखा, अगर मेरे बस में होता, तो मैं ऐसी नहीं होती। लेकिन प्रेग्नेंसी के कारण मेरी बॉडी ने ऐसे ही रिएक्ट किया है। भगवान के लिए प्लीज थोड़ा दयालु होना सीखें।

पिछले साल दिया था बेटी को जन्म

बता दें कि पत्रलेखा और अभिनेता राजकुमार राव ने पिछले साल 15 नवंबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। दोनों ने एक ज्वाइंट पोस्ट के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी थी। पत्रलेखा और राजकुमार राव ने बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा है। एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म फुले में देखा गया था

खेल समाचार

अपने घर में 248 रन चेज नहीं कर पाई बांग्लादेशी टीम

बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में हार मिली है...248 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की पारी 221 रनों पर सिमट गई...

ढाका,17 अप्रैल 2026। बांग्लादेश को किसी भी फॉर्मेट में घर में जाकर हराना मुश्किल होता है। इसके बाद भी न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश दौरे की शुरुआत जीत के साथ की है। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 247 रन बनाए। इसके बाद भी टीम ने मैच को 26 रनों से अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश की पारी 49वें ओवर में 221 रनों पर सिमट गई। 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है।

हेनरी निकोलस और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की फिफ्टी

न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और निकी केली 23 गेंद पर सिर्फ 7 रन बना पाए। शोरिफुल इस्लाम ने उनका विकेट लिया। पावरप्ले में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 38 रन बना। दूसरे विकेट के लिए हेनरी निकोलस और विल यंग के बीच 88 गेंद पर 73 रनों की साझेदारी हुई। निकोलस ने 68 रनों की पारी खेली। यंग के बल्ले से 30 रन निकले। इसके बाद न्यूजीलैंड ने लगातार विकेट खोए। हालांकि 8 चौकों की मदद से डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 59 रन बनाकर टीम को 247 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम और रिषाद होसैन ने 2-2 विकेट लिए।

तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को जीत दिलाई

बांग्लादेश की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और नाथन स्मिथ ने चौथे ओवर में लगातार दो गेंद पर तंजीम हसन तमीम और नजमुल हुसैन शांतो को आउट कर दिया। 21 रन पर दो विकेट गिरने के बाद लिटन दास और सैफ हसन की जोड़ी क्रीज पर टिक गई। दोनों ने 93 रनों की साझेदारी करके टीम को 100 के पार पहुंचाया। 57 रनों की पारी खेलने के बाद हसन विलियम ओरूकी का शिकार बने। लिटन दास 4 रनों से अर्धशतक लगाने से चूक गए। उन्होंने 68 गेंद पर 46 रन बनाए।इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दमदार वापसी की। तौहीद हृदोय ने 60 गेंदों पर 55 रन बनाए लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे। टीम के आखिरी 5 बल्लेबाज 12 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड के लिए तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने 4 और नाथन स्मिथ ने तीन विकेट लिए।

रवांडा 18 अप्रैल को आईसीसी महिला टी 20 आई चैलेंज ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा

किगाली,17 अप्रैल 2026। किगाली महिला क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ते हुए देखने के लिए तैयार है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पहली महिला टी 20 आई चैलेंज ट्रॉफी लॉन्च की है, जो 18 अप्रैल को रवांडा में शुरू होने वाली है। पांच टीमों का यह टूर्नामेंट मेजबान रवांडा और इटली के बीच मैच से शुरू होगा, जबकि उसी दिन नेपाल का मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका से होगा। प्रतियोगिता की पांचवीं टीम,वानुअतु,पहले दिन बाय (बिना खेले अगले दौर में पहुंचना) मिलने के बाद 19 अप्रैल को रवांडा के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। मैच गहांगा क्रिकेट स्टेडियम के दो सटे हुए मैदानों पर खेले जाएंगे।

आईसीसी के अनुसार, एक डबल राउंड-रॉबिन इवेंट के रूप में डिज़ाइन किया गया यह टूर्नामेंट 2 मई तक चलेगा, जो भाग लेने वाली टीमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगा। यह प्रतियोगिता आईसीसी की उस व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य एसोसिएट सदस्य देशों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते मजबूत करना है; यह पिछले साल शुरू की गई इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी जैसे अन्य आयोजनों का पूरक है।

भाग लेने वाली टीमों ने 2025 के क्षेत्रीय महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है। इनमें से प्रत्येक टीम आईसीसी के पांच क्षेत्रों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करती है और ये टीमें इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने से बस कुछ ही कदम दूर रह गई थीं। नेपाल और यूएसए इस टूर्नामेंट में शुरुआती पसंदीदा टीमों के तौर पर उतर रहे हैं, क्योंकि वे इसी साल की शुरुआत में हुए महिला टी 20 विश्व कप ग्लोबल क्वालिफायर में खेल चुके हैं। आईसीसी महिला टी 20 आई रैंकिंग में फिलहाल 21वें स्थान पर मौजूद नेपाल इस प्रतियोगिता में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम है। वहीं,वानुअतु एक डार्क हॉर्स (अप्रत्याशित रूप से सफल होने वाली टीम) साबित हो सकती है। 30वें स्थान पर काबिज इस टीम ने फिजी में हुए ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर के दौरान खुद से ऊंची रैंकिंग वाली टीम इंडोनेशिया को हराकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, जिसके दम पर उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की की। यह चैलेंज ट्रॉफी ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब महिला क्रिकेट का वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार हो रहा है। महिला टी 20 विश्व कप में टीमों की संख्या 2026 में बढ़कर 12 होने वाली है, और 2030 के संस्करण में टीमों की संख्या 16 तक बढ़ने की पुष्टि भी हो चुकी है।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी पहनेगी हरी जर्सी

बेंगलुरु,17 अप्रैल 2026। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी ग्रीन पहल के तहत अपनी मशहूर हरी जर्सी पहनेंगे, जब वे शनिवार को चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग के अपने घरेलू मैच में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेंगे। रीसायकल किए गए मटीरियल से बनी ये जर्सी, फ्रेंचाइजी की सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण-अनुकूलता) के प्रति लगातार प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी हुई हैं। आरसीबी की एक रिलीज़ के अनुसार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दुनिया की एकमात्र कार्बन-न्यूट्रल टी 20 फ्रेंचाइजी है। 2011 में शुरू की गई इस पहल के साथ, आरसीबी अपने सभी कामों में सस्टेनेबिलिटी को शामिल करना जारी रखे हुए है, जिसमें माप,जवाबदेही और प्रशंसकों की भागीदारी पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यह कार्बन-पॉजिटिव बनने की दिशा में काम कर रही है। इस पहल पर बोलते हुए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के राजेश मेनन ने कहा, एक टी 20 फ्रेंचाइजी के तौर पर कार्बन-न्यूट्रल दर्जा हासिल करना,सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हरी जर्सी इसी प्रतिबद्धता को दिखाती हैं, और हमें उम्मीद है कि यह पहल हमारे प्रशंसकों और हितधारकों को और ज़्यादा जम्मिदार और सस्टेनेबल तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। आरसीबी के सस्टेनेबिलिटी प्रयासों का एक अहम हिस्सा,मैच के दिनों में प्रशंसकों के व्यवहार का पूरी तरह से आकलन करना है। स्टेडियम के सभी स्टैंड में किए गए सर्वे के ज़रिए,फ्रेंचाइजी आने-जाने के तरीकों, राइड-शेयरिंग के व्यवहार का अध्ययन कर रही है,और प्रति दर्शक कार्बन उत्सर्जन का अनुमान लगा रही है।

दक्षिण अफ्रीका में उदय मान ने 64 के बेदाग राउंड में ऐस लगाते हुए 6 अंकों की बढ़त बना ली

जोहान्सबर्ग,17 अप्रैल 2026। उदय मान, जिन्होंने पहले दिन शानदार 7-अंडर 65 का स्कोर बनाया था, दूसरे दिन और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8-अंडर 64 का स्कोर जोड़ा। आईजीपीएल इनविटेशनल दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राउंड में उनके इस स्कोर में एक होल-इन-वन भी शामिल था। मशहूर रॉयल जोहान्सबर्ग के वेस्ट कोर्स पर खेलते हुए, ओलंपियन मान लगातार दूसरे दिन बोगी-फ्री रहे। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, वह कुल 15-अंडर के स्कोर पर पहुँच गए और पार से नीचे दोहरे अंकों में पहुँचने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए। मान अब अपने पहले आईजीपीएल खिताब की तलाश में बाकी खिलाड़ियों से छह शॉट आगे चल रहे हैं। मान से पीछे, संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर तीन बेहद प्रेरित खिलाड़ी हैं: मानव शाह (65-70),पुखराज सिंह गिल (66-69) और गगनजीत भुल्लर (67-68)। फिर भी, उनमें

से हर कोई जानता है कि एकाग्र और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मान की छह शॉट की बढ़त को पार करना एक मुश्किल काम होगा। स्थानीय दक्षिण अफ्रीकी स्टार मुसिवालो नेथुन्ज़वी (69-67) अकेले पाँचवें स्थान पर रहे, जबकि नए पेशेवर खिलाड़ी दानिश वर्मा (70-67) और एक अन्य दक्षिण अफ्रीकी गोल्फर, एलेसियो ग्राज़ियानी (72-65) संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे।

पहले दिन के तीन शीर्ष खिलाड़ियोंमें से एक, मिलिंद सोनी, बीच के राउंड में लड़खड़ा गए। 11वें और 12वें होल पर बोगी और डबल बोगी के कारण उन्होंने 73 का स्कोर बनाया। इसके चलते वह कुल 6-अंडर के स्कोर के साथ राघव चुघ (69-69) और करनदीप कोचर (67-71) के साथ संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर खिसक गए। पिछले हफ़्ते के उपविजेता, वीर गणपति (70-70), हर्षजीत सिंह सेठी (70-70), वरुण पारिख (70-70) और बाएं हाथ के खिलाड़ी कार्तिक शर्मा (69-71) के साथ संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर रहे। इन सभी का कुल स्कोर 4-अंडर था। इस टूर्नामेंट में स्कोरिंग काफी कम रही है; 36 होल के बाद 27 खिलाड़ी पार या उससे बेहतर स्कोर पर हैं,और इस प्रतियोगिता में अभी एक राउंड और बाकी है।

ऊबर कप फ़ाइनल्स 2026 के लिए भारतीय टीम में गायत्री-जूली की जगह श्रुति-प्रिया की जोड़ी शामिल

नई दिल्ली,17 अप्रैल 2026। थॉमस और उबर कप फ़ाइनल्स 2026 के लिए भारत की तैयारियों को एक झटका लगा है, क्योंकि डबल्स स्पेशलिस्ट ट्रीसा जॉली चोट के कारण बाहर हो गई हैं, जिससे महिला टीम में आखिरी समय में बदलाव करना पड़ा है। गायत्री गोपीचंद भी इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी; उनकी जगह भारतीय टीम में श्रुति मिश्रा और प्रिया कोंजेंगबम को शामिल किया गया है। बीएआई मीडिया ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। यह नई जोड़ी महिला डबल्स लाइनअप में कविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो के साथ शामिल होगी। सिंगल्स में, भारत युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण पर निर्भर रहेगा,जिसकी अगुवाई पीव्ही सिंधु करेंगी। उनके साथ उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और इशरानी बरुआ जैसे उभरते हुए नाम भी शामिल हैं।

भारत के पूरे अभियान की अगुवाई दोनों प्रतियोगिताओं के शीर्ष शटलर करेंगे। थॉमस कप में लक्ष्य सेन और पुरुषों की डबल्स की मशहूर जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी टीम की कमान संभालेंगे। पुरुष टीम में अनुभवी खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और HS प्रणॉय भी शामिल हैं, जबकि युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज सिंगल्स यूनिट को और मज़बूती देंगे। डबल्स में,

हरिहरन अमसकारुनन, MR अर्जुन और ध्रुव कपिला मिलकर एक संतुलित लाइनअप पूरा करते हैं। खिलाड़ियों का चयन मुख्य रूप से 10 मार्च तक की रैंकिंग के आधार पर किया गया था, जिसमें शीर्ष पांच सिंगल्स खिलाड़ियों और शीर्ष दो डबल्स जोड़ियों को सीधे जगह मिली। रणनीतिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त खिलाड़ियों का भी चयन किया गया;कपिला और क्रास्टो जैसे खिलाड़ियों को अलग-अलग फ़ॉर्मेट में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए महत्व दिया गया। 2026 थॉमस और उबर कप फ़ाइनल्स 24 अप्रैल से 3 मई तक डेनमार्क के हॉर्सेंस में आयोजित किए जाएंगे। महिला डबल्स जोड़ी में आखिरी समय में हुए बदलावों के बावजूद,भारत इस प्रतियोगिता में एक मज़बूत चुनौती पेश करने का लक्ष्य रखेगा।

C M Y K

5 मई तक आखिरी मौका...नहीं भरा ई-चालान तो सड़क पर ही जब्त होगा वाहन,कोर्ट की कार्रवाई तय! '

रायपुर,17 अप्रैल 2026। हजारों वाहन मालिकों के लिए राहत और चेतावनी दोनों साथ आई है,यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के ई-चालान अब तक लंबित हैं और कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं, उनके लिए मई में लगने वाली लोक अदालत आखिरी मौका साबित हो सकती है, 17 अप्रैल 2026 को यातायात कमिश्नरेट रायपुर की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जारी हुए सभी लंबित ई-चालानों का निराकरण लोक अदालत में किया जाएगा लेकिन इसके लिए 5 मई 2026 तक नजदीकी यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के मामला लोक अदालत में जाएगा ही नहीं और फिर सीधे न्यायालयीन प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी, पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने सख्त निर्देश देते हुए साफ कहा है कि लोक अदालत के बाद भी जिन मामलों का निराकरण नहीं होगा, ऐसे वाहन सीधे जब्त किए जाएंगे और कोर्ट में पेश किए जाएंगे जिससे वाहन मालिकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं, यातायात पुलिस अब लंबित चालानों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है, संबंधित वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल के जरिए सूचना दी जाएगी और व्हाट्सएप पर नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि कोई यह न कह सके कि उसे जानकारी नहीं थी, शहर के 9 प्रमुख यातायात थाना–तेलीबांधा,भाठागांव,शारदा चौक, फाफाडीह,भनपुरी,टाटीबंध,पंडरी,पचपेड़ीनाका और कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय–को रजिस्ट्रेशन के लिए चिन्हित किया गया है जहां जाकर वाहन मालिक अपने लंबित प्रकरण को लोक अदालत में पेश करवाने के लिए दर्ज करा सकते हैं, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर ई-चालान का निराकरण नहीं कराया गया तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि वाहन से जुड़े सभी काम भी अटक सकते हैं, यानी न फिटनेस, न ट्रांसफर, न कोई अन्य सुविधा, कुल मिलाकर यह एक ऐसा अलर्ट है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है– समय रहते चालान भरिए, वरना सड़क से सीधे कोर्ट तक का सफर तय करना पड़ेगा।

त्वचा दान कर शुक्ला परिवार ने दी मानवता की मिसाल

दुर्ग,17 अप्रैल 2026। भिलाई नेहरू नगर निवासी डॉ. रवि शुक्ला ने अपनी माताजी रानी शुक्ला के निधन के उपरांत परिवारजनों मधु शुक्ला, नीलू त्रिवेदी,डॉ. मंजू शुक्ला एवं डॉ. मंजरी शुक्ला–की सहमति से त्वचा दान कर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान नवदृष्टि फाउंडेशन के मुकेश आढ़तिया,कुलवंत भाटिया, राज आढ़तिया, प्रभु दयाल उजाला एवं राजेश पारख पल्स हॉस्पिटल में उपस्थित रहे और पूरी त्वचा दान प्रक्रिया में सहयोग किया। सेक्टर-9 हॉस्पिटल की बर्न यूनिट टीम के डॉ. अनिरुद्ध मेने,सुनीता साहू, विनीत कुमार,शिवांगी साहू,चमेली एवं विक्की सर ने सफलतापूर्वक त्वचा संग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की। डॉ. रवि शुक्ला ने बताया कि डॉक्टर परिवार से होने के कारण वे नेत्रदान एवं त्वचा दान के महत्व को भली-भांति समझते हैं। इसी सोच के साथ परिवार ने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया,जिससे उनकी माताजी का जीवन और भी सार्थक बन सका। उन्होंने समाज में इस विषय पर अधिक जागरूकता की आवश्यकता भी बताई। नवदृष्टि फाउंडेशन के मुकेश आढ़तिया ने जानकारी दी कि शुक्ला परिवार ने त्वचा दान के साथ-साथ नेत्रदान के लिए भी सहमति दी थी,लेकिन तकनीकी कारणों से नेत्रदान संभव नहीं हो सका। कुलवंत भाटिया ने कहा कि डॉ. रवि शुक्ला क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और उनके परिवार के इस निर्णय से समाज में त्वचा दान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तथा भविष्य में इसका लाभ अनेक मरीजों को मिलेगा।

अजीत डोभाल ने की छत्तीसगढ़ के आईपीएस संतोष कुमार सिंह की तारीफ

रायपुर,17 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसर और रायपुर पुलिस मुख्यालय के DIG डॉ. संतोष कुमार सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एकेडमिक अचीवमेंट से छत्तीसगढ़ और देश का मान बढ़ाया है। उनकी हालिया प्रकाशित रिसर्च बुक 'Institutionalization of PeacebuildingÑ Functioning of the United Nations Peacebuilding Commission in Sierra Leone & Burundi' की देश के टॉप ऑफिशियल्स ने जमकर तारीफ की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री कार्यालय ने डॉ. सिंह को पत्र लिखकर उनके काम की सराहना की है। डॉ. संतोष कुमार सिंह की यह बुक मुख्य रूप से अफ्रीका के दो देशों सिएरा लियोन और बुरुंडी में संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना आयोग की भूमिका पर आधारित है। यह बुक इंटरनेशनल लेवल पर शांति बहाली के लिए किए जा रहे एफर्ट्स और उसमें आने वाले इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस का एक डिटेल एनालिसिस करती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डॉ. संतोष कुमार सिंह को पत्र लिखकर उनके डीप रिसर्च वर्क की तारीफ की है। डोभाल ने लिखा कि यह बुक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के काम करने के तरीके को समझने के लिए एक शानदार बैकग्राउंड तैयार करती है।

पावर प्लांट हादसा : मृतकों की संख्या 21 हुई

सरकार ने वेदांता ब्लास्ट की कमिश्नर जांच के लिए तय किये बिंदु...

सक्ती,17 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ सक्ती जिले के ग्राम सिंघीतराई में स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को भीषण विस्फोट हुआ था। उस दिन 14 लोगों की जान गई थी। दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़ कर 20 पहुंच गया था। 17 अप्रैल को एक और मौत के बाद आंकड़ा 21 जा पहुंचा है। खबर है कि इस बार मध्यप्रदेश के सिंगरौली निवासी किस्मत अली की सांस थम गई है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। इस तरह अब पांच राज्यों के बाद घटना में छठवें राज्य का भी नाम जुड़ गया है। 20 श्रमिक मूलतः पांच राज्यों छत्तीसगढ़,

पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, झारखंड और बिहार के हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पांच श्रमिक पश्चिम बंगाल के मारे गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के पांच श्रमिकों की जान जा चुकी है। अब भी रायगढ़ और रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में 15 श्रमिकों का उपचार जारी है। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वेदांता प्रबंधन ने इन जख्मी श्रमिकों की सेहत पर विशेष रूप से नजर रख रहा है।

बिलासपुर आयुक्त सुनील जैन करेंगे वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच

राज्य सरकार ने सक्ती जिले के डभरा तहसील अंतर्गत सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं। बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील जैन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिवस के भीतर जांच पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करें।

चेयरमैन समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज

वेदांता हादसे को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में कंपनी के चेयरमैन समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना को गंभीर मानते हुए सरकार ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद ही स्पष्ट कर दिया गया था कि मामले की गहन जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और हादसा बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के तहत जवाब देना होगा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि एफआईआर ऑनलाइन उपलब्ध है और यदि उन्हें जानकारी चाहिए तो लिंक देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। हादसे को लेकर पूरे राज्य में चिंता का माहौल है और लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा विभाग में 45 प्रोफेसरों के सीआर के फोल्डर गायब...!

प्राचार्य के पद पर होना है प्रमोशन

रायपुर,17 अप्रैल 2026। उच्च शिक्षा के चार दर्जन प्रोफेसरों की सालाना गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) गायब होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। संचालनालय ने उच्च शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर इन सभी प्रोफेसरों के एसीआर का फोल्डर उपलब्ध कराने कहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसरों के गोपनीय प्रतिवेदन संचालनालय में उपलब्ध नहीं हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी 45 प्रोफेसर, प्राचार्य पदोन्नत होने हैं। इस पत्र के खुलासे के बाद प्रोफेसरों के साथ संचालनालय से लेकर मंत्रालय तक हलचल मच गई है। प्रोफेसर तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। बता दें कि विभाग में इन दिनों सौ से अधिक प्राचार्यों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, और जिनके फाइल गायब हुए हैं उनकी भी पदोन्नति होनी है। फाइल

नहीं मिली तो पदोन्नति की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक,कलेक्टर की अनुमति बिना नहीं मिलेगी छुट्टी

रायपुर,17 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक कसावट तेज कर दी है। इसके तहत अब जिले के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति के अवकाश नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा क्योंकि जनगणना एक विशाल प्रक्रिया है जिसमें हजारों शिक्षकों और सरकारी कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। छुट्टियों पर इस सख्ती का उद्देश्य डेटा संग्रह की शुद्धता सुनिश्चित करना और केंद्र द्वारा तय की गई समय सीमा का पालन करना है। राज्य शासन के निर्देशानुसार, जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर सहित सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। फील्ड वर्क के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने स्तर पर अवकाश स्वीकृत न करें। किसी भी आपात स्थिति में यदि कर्मचारी को छुट्टी की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित कारणों के साथ अपना आवेदन सीधे जिला कलेक्टर या संबंधित नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करना और हाउसिंग सेंसस का कार्य शामिल है। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में जनगणना कार्य के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। आने वाले हफ्तों में ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों का सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि मानसून की शुरुआत से पहले डिजिटल डेटा एंट्री का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही की समस्या आड़े न आए।

1.22 करोड़ का गांजा जब्त,एक आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर,17 अप्रैल 2026। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रतनपुर पुलिस और एसीसीयू (एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 245 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 1.22 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 अप्रैल को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मारुति अर्टिगा (क्रमांक CG 04 QD 7255) में भारी मात्रा में गांजा कटघोरा से मरवाही होते हुए मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल रतनपुर पुलिस और ACC की टीम ने नेशनल हाईवे स्थित नवापारा चौक भेड़ी मुंडा के पास घेराबंदी

की। चेकिंग के दौरान संदिग्ध अर्टिगा कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 245 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन मारुति अर्टिगा (कीमत लगभग 8 लाख रुपए) को भी जब्त किया गया। कुल जब्ती की कीमत 1 करोड़ 30 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी अमित कुमार केवट (33 वर्ष), निवासी भुतहीटोला, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना रतनपुर में नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध तस्करी के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पति के सुसाइड में पत्नी का कथित बॉयफ्रेंड क्यों हुआ 'बरी' सुप्रीम कोर्ट ने पलटा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला

रायपुर,17 अप्रैल 2026। क्या विवाहेत्तर संबंध को आत्महत्या के लिए उकसाने के तौर पर देखा जा सकता है? इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी या पति के विवाहेतर संबंधों के चलते तनाव में चला जाता है और फिर आत्महत्या कर लेता है तो लाइफ पार्टनर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं बनता है। इसका मतलब लाइफ पार्टनर पर इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है कि उसके अफेयर के चलते तनाव में आकर पीड़ित ने आत्महत्या की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के उस फैसले को पलट दिया,जिसमें आत्महत्या के लिए पत्नी के प्रेमी को दोषी ठहराया गया था। दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमी को राहत देते हुए उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे को निरस्त कर दिया। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अतुल चंदुरकर की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अपराध साबित करने के लिए आरोपी की नीयत साबित करना जरूरी है। अपनी टिप्पणी में सर्वोच्च कोर्ट ने केवल लव अफेयर की टेंशन या मानसिक पीड़ा ही कारण नहीं है। वजह ऐसी होनी चाहिए, जिससे जाहिर हो कि कोई रास्ता नहीं बचा है। मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में शादीशुदा शख्स ने अपनी पत्नी के लव अफेयर के चलते आत्महत्या कर ली थी। परिजन ने आरोप लगाया कि पत्नी के बॉयफ्रेंड की मौजूदगी में पति का अपमान हुआ। इसके चलते वह मानसिक तनाव में चला गया। आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने सवालिया लहजे में पूछा कि इससे कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि लव अफेयर के चलते पत्नी के कथित बॉयफ्रेंड ने उसके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया।

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ याचिका

मसीही समाज ने अधिनियम को हाईकोर्ट में दी चुनौती, कहा- अवैध धर्मांतरण पर उम्रकैद गलत

बिलासपुर,17 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026' को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस विधेयक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कानून के कई कड़े प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। दरअसल, राज्य सरकार के इस विधेयक में जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के अनुसार अवैध धर्मांतरण पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें आर्थिक प्रलोभन, दबाव या छल से धर्म बदलवाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही

संगठित या बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने पर और सख्त दंड देने का उल्लेख है। राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून धर्मांतरण पर रोक नहीं, बल्कि गैर-कानूनी तरीकों पर नियंत्रण के लिए लाया गया है।

कड़े सजा के प्रावधानों को दी चुनौती : मसीही समाज के क्रिस्टोफर पॉल ने अपनी याचिका में कहा कि, यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इस कानून में अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास जैसी सजा देना असंवैधानिक है। इस नियम को चुनौती देते हुए कहा कि, कानून की परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, जिससे मनमानी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। यह व्यक्तिगत निजता और आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। फिलहाल, हाईकोर्ट में अभी याचिका लगी है। लेकिन, सुनवाई के लिए अभी तारीख तय नहीं की गई है।

सरकार टारगेट कर बना सकती है हथियार

याचिकाकर्ता का कहना है कि, इस अधिनियम को राज्य सरकार टारगेट कर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। मसीही समाज की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इस कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए हो सकता है। इसके तहत सामाजिक संगठनों में आशंका है कि कठोर सजा और अस्पष्ट शब्दावली से दुरुपयोग हो सकता है।

छत्तीसगढ़ सीआईसी नियुक्ति विवाद: हाईकोर्ट ने हटाई रोक

30 साल के अनुभव वाली शर्त को माना सही,जल्द होगी नियुक्ति

रायपुर,17 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर विराम लगा दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने नियुक्ति के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है।

बीच में बदले गए नियम?

दरअसल, सरकार ने मार्च 2025 में जब विज्ञापन निकाला था, तब अनुभव की कोई शर्त नहीं थी।

लेकिन मई में इंटरव्यू कॉल लेटर के दौरान 25 और 30 साल के अनुभव की नई शर्त जोड़ दी गई। याचिकाकर्ताओं का

आरोप था कि बीच में नियम बदले गए। एक बड़ा आरोप यह भी लगा कि सर्च कमेटी में शामिल आईएएस अफसर अपने ही उन सीनियर अफसरों का इंटरव्यू ले रहे थे, जिनके नीचे वे कभी काम कर चुके हैं। 172 वैध आवेदकों में से इस शर्त की वजह से सिर्फ 51 लोग ही इंटरव्यू की रेस में बचे थे।

हाईकोर्ट ने कहा...

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के पक्ष को सही ठहराया है। कोर्ट ने साफ किया कि शॉर्टलिस्टिंग जायज है, इतने ज्यादा आवेदकों का इंटरव्यू लेना मुमकिन नहीं था, इसलिए अनुभव के आधार पर छंटनी करना गलत नहीं है। सीआईसी का पद हाईकोर्ट जज के बराबर का होता है, इसलिए 25-30 साल का अनुभव मांगना पूरी तरह तर्कसंगत है। इसी के साथ ही इस मामले में 29 मई से लगी रोक अब हट चुकी है, जिससे नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 11 नवंबर 2022 से खाली है। आयोग में फिलहाल सिर्फ एक सदस्य होने के कारण आरटीआई की 10 हजार से ज्यादा अपीलें धूल फांक रही हैं।

सोशल मीडिया से सट्टा साम्राज्य...रायपुर का इन्फ्लुएंसर निकला '3 STUMPS' सिंडिकेट का मास्टरमाइंड

रायपुर,17 अप्रैल 2026। रायपुर से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी पर ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने महादेव बुक की तर्ज पर '3 STUMPS' नाम की वेबसाइट बनाकर आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाने का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इस मामले में 13 अप्रैल को गंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि बाबू खेमानी विदेश में बैठकर इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। रायपुर के साथ-साथ पुणे, मुंबई और गोवा जैसे शहरों में उसके रिश्तेदार और करीबी लोग पैनल चलाकर इस अवैध कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे। हाल ही में रायपुर पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। सूत्रों के मुताबिक, यह सिंडिकेट बेहद संगठित तरीके से काम करता था। अलग-अलग शहरों में ऑपरेटर यूजर्स को जोड़ने, सट्टा लगवाने और पैसों के लेन-देन की जिम्मेदारी संभालते थे। ट्रांजेक्शन के लिए म्यूल खातों का इस्तेमाल किया जाता था,जिससे पैसों का ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस अवैध नेटवर्क के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां युवाओं को आकर्षित कर इस जाल में फंसाया जा रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल सट्टा सिंडिकेट से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक–अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:–13/सरगुजा/डीएन/2026-2028–मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)